महाकालेश्वर जी का संध्या काल आरती श्रृंगार दर्शन

केंद्र और राज्य शासन से विज्ञापन के लिए अनुमोदित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

17 वर्षों से निरंतर....

Website:- www.malwaherald.com

RNI No. MPHIN/2010/33238
dainikmalwaherald@yahoo.com
malwaherald@gmail.com

माँ दुर्गा का सप्त ईश्वरीय स्वरुप

माँ कालरात्रि

मालवा हेराल्ड

वर्ष : 17 अंक : 128 | उज्जैन, शनिवार 17 अक्टूबर 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य-1 रुपए

न्यूज ब्रीफ

केरलम में कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालकर जताया विरोध

तिरुवनंतपुरम/ जीएनएस। केरलम के पलक्कड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बाकायदा सीईसी का चिता सजाकर, माला चढ़ाई गई तस्वीर रखकर अंतिम संस्कार से जुड़े रीति-रिवाजों का मंचन किया और बाद में बची हुई राख को एक शौचालय में बहा दिया। यह प्रदर्शन पलक्कड़ शहर के स्टेडियम बस स्टैंड के पास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था। पार्टी कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) कार्यालय से एक प्रतीकात्मक अर्थी लेकर बस स्टैंड तक पहुंचे। वहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की माला चढ़ी तस्वीर रखकर हिंदू अंतिम संस्कार की तरह रस्में निभाई, फिर प्रतीकात्मक चिता को आग के हवाले कर दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन का सबसे विवादित पहलू चिता जलने के बाद सामने आया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने वहां से राख एकत्र की और उसे मुख्य चुनाव आयुक्त का विरोध जताते हुए एक शौचालय में बहा दिया। इस कदम के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी के दोहरे रुख पर भी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल, कुछ समय पहले पलक्कड़ के ही गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ जब वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई ने इसी तरह का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया था, तब कांग्रेस नेताओं ने उसकी कड़ी आलोचना की थी। अब वही कांग्रेस कार्यकर्ता देश के एक प्रमुख संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ उसी तरह का प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं।

जग्गा जासूस, राजनाथ सिंह के सत्ता परिवर्तन वाले दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज

नई दिल्ली/ जीएनएस। प्रशांत भूषण के सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर राजनाथ सिंह की आपत्ति को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का लक्ष्य स्पष्ट है और वो चुनाव के जरिए सरकार को हराना चाहते हैं। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है शीर्षक से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खेड़ा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, हम अपना लक्ष्य फिर से दोहरा रहे हैं.. हमें इस सरकार को हराना है और इस व्यवस्था को बदलना है। तो फिर राजनाथ सिंह जग्गा जासूस क्यों बन गए हैं? पवन खेड़ा ने तर्क दिया कि चुनावों के माध्यम से सरकार बदलना लोकतंत्र का एक सामान्य हिस्सा है। उन्होंने 1977 का जिक्र करते हुए कहा, हम तो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज करेंगे साहब... 77 में क्या हुआ था रिजीम नहीं बदला था? हर बार जब कोई विपक्ष सड़क पर आता है, कोई आंदोलन होता है.. तो रिजीम बदलता है। भारत जैसे लोकतंत्र में रिजीम कैसे बदलता है? चुनावों के जरिएज चुनाव के जरिए ही तो रिजीम बदलना मकसद होता है विपक्ष का, और क्या मकसद होता हैज खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, वह लोकतंत्र का पालन करने की आदत भूल चुकी है।प्रशांत भूषण के बयान को लेकर बीजेपी विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है। बीजेपी की तरफ से शुक्रवार को राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों ने सत्ता परिवर्तन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी यह लड़ाई चुनाव सुधार या स्ढ्ढक्रसे जुड़े मुद्दों के लिए नहीं हैं। स्ढ्ढक्र और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था और कहा कि अगर सरकार को यह लगता है कि यह सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है तो हां रिजीम चेंज करना चाहते हैं।

जनसमस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से करें : मुख्यमंत्री

उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण दिलाएं

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम समाधान कार्यक्रम में विभिन्न शिकायतकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से करें। शिकायतों का प्रारंभिक स्तर पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

समाधान कार्यक्रम में लाड़ली लक्ष्मी योजना, आवास योजना के बिलों में गड़बड़ी, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना तथा नल-जल योजना से संबंधित शिकायतों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी डीपीओ श्री ओ.पी. पांडे को संबंधित प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री अमर दाहिया को नल-जल योजना से संबंधित प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए कहा। ऊर्जा विभाग के उप महाप्रबंधक श्री रघुवीर सिंह को शिकायत का समय पर निराकरण नहीं होने पर लघु शास्ति अधिरोपित करने के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त श्री सत्येन्द्र धाकरे को नगरीय निकायों से संबंधित प्रकरणों का अभिलेख तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा आमजन से जुड़े मूलभूत विषयों और शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि समस्याओं का प्रारंभिक स्तर पर ही समाधान कर दिया जाए, तो शिकायतों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के कार्यों की निगरानी की जाती है और प्रस्तुत प्रतिवेदनों में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन और प्रशासन का मूल उद्देश्य जनता के हित में कार्य करना तथा उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करना है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी न हो और प्रत्येक शिकायत का निराकरण संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ किया जाए।

जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनविश्वास अभियान के अंतर्गत मुरैना कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, कृषि एवं पशुपालन, सहकारिता, पर्यटन, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन तथा जनसमस्याओं के निराकरण सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह समिति जिले के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। जनप्रतिनिधि जिले की आवश्यकताओं, समस्याओं, संभावनाओं और विकास से संबंधित अपने सुझाव समिति के माध्यम से प्रस्तुत करें, ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं तैयार कर उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक जिले को विकास का एक आदर्श मॉडल बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विकास कार्यों की समीक्षा करें, स्थानीय समस्याओं एवं कठिनाइयों को समझें तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और जनहित में नवाचार करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ आमजन तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुरैना जिले में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां स्थापित हो रही औद्योगिक इकाइयों से स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रस्तावित उद्योगों से उनकी मानव संसाधन संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली जाए और उसी के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया जाए, ताकि इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ होने के साथ ही प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्लास विनिर्माण इकाई का उदाहरण देते हुए कहा कि इस प्रकार की बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करती हैं। ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन तैयार करना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पराली से औद्योगिक उत्पाद तैयार करने वाली इकाइयों की सराहना करते हुए कहा कि कृषि अपशिष्ट का उपयोग कर नए उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सरकार ने बदल दिया जनगणना का नियम, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे इन लोगों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली/ जीएनएस। केंद्र सरकार ने जनगणना नियम, 1990 में संशोधन किया है। इसके तहत जनगणना करने वालों (एन्यूमेरेटर) के रूप में काम करने के लिए पात्र लोगों के दायरे को बढ़ा दिया गया है।

अब इसमें सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, सरकारी अधिकारी और क्लर्क आदि भी शामिल हो गए हैं।

केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना- गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नए जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है।

अधिसूचना के अनुसार, सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, सहायता प्राप्त या बिना सहायता वाली निजी संस्थाओं, सोसायटियों या ट्रस्टों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, जनगणना करने वाले एन्यूमेरेटर के रूप में काम कर सकते हैं।

संशोधित नियमों में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों और विभिन्न प्रतिष्ठानों के क्लर्क और अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। इन प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैधानिक निकाय, बैंक, कंपनियां, संस्थान, सोसायटियां और ट्रस्ट आते हैं।राज्य सरकारों को भी छूट इसके अलावा, ये नियम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को यह छूट देते हैं कि वे किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को भी जनगणना करने वाले एन्यूमेरेटर के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं। इस संशोधन के जरिए जनगणना नियम, 1990 के नियम 3 के तहत दी गई तालिका में क्रम संख्या 5 पर मौजूद प्रविष्टियों को बदल दिया गया है, ताकि पात्र श्रेणियों को स्पष्ट किया जा सके।

TMC के नाम और चुनाव चिह्न पर किसका हक? 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा चुनाव आयोग; दोनों पक्षों को बुलावा

नई दिल्ली/ जीएनएस। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों विरोधी गुटों को 30 अक्टूबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया है। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के दौरान दोनों धड़ों पर पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के बाद यह पहली आधिकारिक सुनवाई होगी।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, दोनों गुटों के बीच पार्टी के अधिकार और प्रतीक को लेकर चल रहे विवाद पर 30 अक्टूबर को विस्तार से विचार किया जाएगा। आयोग ने दोनों पक्षों को अपने-अपने दस्तावेज और दावे पेश करने के निर्देश दिए हैं ताकि पार्टी के असली हकदार का निर्धारण किया जा सके।

इससे पहले 17 सितंबर को चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद आयोग ने कहा था कि इस मामले का निपटारा चुनाव चिह्न आदेश, 1968 के प्रावधानों के तहत ठोस जांच के बाद ही किया जा सकता है। अंतरिम आदेश के तहत चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल उपचुनाव के दौरान दोनों ही गुटों पर पार्टी के मूल नाम तृणमूल कांग्रेस और उसके चुनाव चिह्न फूल और घास का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी।

उपचुनाव में उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए आयोग ने दोनों धड़ों को अस्थायी तौर पर अलग-अलग नए नाम और अलग चुनाव चिह्न आवंटित किए थे।

कब होगी भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील? निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब

नई दिल्ली/ जीएनएस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को वैश्विक व्यापार तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के हित में जल्द से जल्द अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण तय हो चुका है और अभी इसका कानूनी मसौदा तैयार किया जा रहा है।

चीन के साथ व्यापार पर सीतारमण ने कहा कि बीजिंग के साथ वर्षों की बातचीत के बावजूद बढ़ता व्यापार असंतुलन और भारतीय उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच पर लगातार लगी पाबंदियां बड़ी चिंता का विषय बनी हुई हैं।

थाइलैंड के बैंकाक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान अटलांटिक काउंसिल के साथ बातचीत में सीतारमण ने कहा कि भारत ने लगातार चीन में जेनेरिक दवाओं, गोमांस, सब्जियों और अन्य जल्दी खराब होने वाले सामानों के लिए बाजार तक पहुंच मांगी है, लेकिन सालों की बातचीत के बाद भी इसमें सीमित प्रगति हुई है। उन्होंने कहा, भारत और चीन के बीच व्यापार में गैर-शुल्क बाधाएं सबसे बड़ी रुकावट हैं। उन्होंने कहा कि बड़े व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों पर दंडात्मक शुल्क लगाने का तरीका नहीं अपनाया है, बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने को प्राथमिकता दी है, भले ही इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाए।

ब्रिक्स के बारे में सीतारमण ने कहा कि इस समूह को किसी देश या गुट का मुकाबला करने के मंच के बजाय, अपने लोगों के कल्याण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनी एक साझेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ब्रिक्स का इरादा दूसरों का मुकाबला करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से साझेदारी को मजबूत करना है।

हमसे सामान आयात करने वाले देश रुपये में भुगतान करें- वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत उन सहयोगी देशों के साथ रुपये में व्यापार करना चाहता है जो विदेशी मुद्रा की कमी का सामना कर रहे हैं। इससे वे जरूरी सामानों का आयात जारी रख सकेंगे। उन्होंने कहा, हम यह चाहते हैं कि जो देश हमसे सामान आयात करते हैं वे अपना भुगतान रुपये में करें।

सीतारमण ने कहा कि फिलहाल आसियान देशों के साथ जो हमारा व्यापार समझौता वह भारत के लिए काफी नुकसानदेह है। अगर इससे आसियान को लाभ होता है तो हमें खुशी होगी, लेकिन हम उन चिंताओं को भी दूर करना चाहते हैं जिनका सामना हम (आयातकों के रूप में), हमारे बाजार और हमारे निर्माता कर रहे हैं। दोनों पक्ष इस समझौते की समीक्षा कर रहे हैं। भारत इस समझौते को जारी तो रखना चाहता है, लेकिन कुछ बदलावों के साथ।

वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में बड़े सुधारों की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को खोलने और वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, लेकिन स्थानीय निकायों को भी विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की अपनी क्षमता को मजबूत करने की जरूरत है।

दिल्ली में यूएपीए मामले में अतहर खान को राहत नही

नई दिल्ली/ जीएनएस। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी, 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की बड़ी साजिश से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में आरोपित अतहर खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को चार सप्ताह के लिए टाल दी।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू के यह बताने पर सुनवाई स्थगित कर दी कि मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने खान को दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी।

सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले खान की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। खान ने सात जुलाई के दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसे जमानत देने से इन्कार कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अतहर की अपील खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 29 जनवरी को उसे राहत देने से इन्कार कर दिया था।

विरोध प्रदर्शनों का असली चेहरा आया सामने, धर्मेंद्र प्रधान ने सत्ता परिवर्तन वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी पर साधा निशाना

नई दिल्ली/ जीएनएस। जुलाई में पेपर लीक को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और विपक्षी दल भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए छात्रों का इस्तेमाल एक ढाल के रूप में कर रहे हैं।

प्रधान के अनुसार, इस तरह के आंदोलन देश में अराजकता फैलाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है।

बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन का दिया हवाला- एक्स पर अपनी पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने बांग्लादेश में त्रद्गठ्ठ ' के विद्रोह और वहां सत्ता परिवर्तन की मांग का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित और छात्रों के कल्याण के नाम पर शुरू किए गए इन प्रदर्शनों का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो लोग विदेशों ताकतों के सहारे सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भारत में सत्ता परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए ही संभव है, और देश की जनता इस अलोकतांत्रिक मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

प्रधान ने राहुल गांधी पर चुनावी नतीजों के मनमुताबिक न आने पर बार-बार जनता के जनादेश का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान को हाथ में लेकर घूमने वाले, लेकिन असल में संविधान-विरोधी राहुल गांधी सत्ता की लालसा में लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र के प्रति विपक्ष के इस रवैये को बेहद शर्मनाक करार दिया।

कांग्रेस ने अपनी मांग का किया बचाव- दूसरी ओर, कांग्रेस ने अपनी सत्ता परिवर्तन की मांग का बचाव किया। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी नेताओं के उन आरोपों को खारिज किया, जिनमें विरोध-प्रदर्शनों की तुलना बांग्लादेश जैसी उथल-पुथल से की गई थी।

शेयर हेरफेर मामले में महाराष्ट्र और गुजरात में ED की छापामारी, लाखों निवेशकों को उठाना पड़ा था नुकसान

नई दिल्ली/ जीएनएस। शेयर में हेरफेर की वजह से प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र और गुजरात में छापामारी की। शुक्रवार को इन दोनों राज्यों के कई शहरों में तलाशी अभियान चला कर कुछ अहम दस्तावेजों को जब्त किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई दो लिस्टेड कंपनियों के शेयर में कथित हेरफेर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। इस मामले में कंपनियों से जुड़े लोगों पर आरोप है कि उन्होंने जबरन कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाए। जिन कंपनियों पर कार्रवाई की गई हो उनमें से एक महाराष्ट्र और दूसरी गुजरात में काम करती है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच दोनों कंपनियों ने खास लोगों और इकाइयों को 3.5 करोड़ से अधिक शेयर और कन्वर्टिबल वारंट जारी किए। वहीं इन शेयरों के लिए अदा किए गए पैसे कंपनी, कर्जदाताओं और आपस से जुड़े लोगों के एक छोटे से समूह से आया था।

कंपनी के हेरफेर के बारे में खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि शेयरों की कीमतों को लगातार बढ़ाया गया, जबकि ये शेयर मुख्य रूप से उन्हीं लोगों के पास बने रहे। इस वजह से अनुमान के मुताबिक एक लाख से ज्यादा छोटे निवेशकों को घाटा हुआ। घाटे की मुख्य वजह ये रही कि उनके शेयर बेचे ही नहीं जा सके।

तलाशी का अभियान गांधीनगर, अहमदाबाद, मुंबई, नासिक, सूरत और भावनगर में चला, जहां दोनों कंपनियों के प्रमोटरों के घरों की तलाशी ली गई। ईडी के अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों को कम कीमत पर शेयर दिए गए थे, उनके ठिकानों, पर भी तलाशी अभियान चलाया गया।

इंदौर में 'द मैन बिहाइंड द वर्डिक्ट' कार्यक्रम में बोले उज्जवल निकम, 'सच के साथ साहस से लड़ना भी राष्ट्रभक्ति है'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, निकम के कानूनी योगदान की सराहना की; न्यायपालिका की अतिरिक्त टिप्पणियों पर भी बोले वरिष्ठ अधिवक्ता

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पद्मश्री एवं राज्यसभा सांसद और देश के चर्चित विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने कहा कि सच के साथ साहसपूर्वक खड़े रहना भी राष्ट्रभक्ति है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कानून, न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि गंभीर आपराधिक मामलों में अभियोजन की जिम्मेदारी केवल अदालत में पक्ष रखने तक सीमित नहीं होती, बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्याय सुनिश्चित करने की होती है। वे गुरुवार को इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में संस्था सार्थक द्वारा आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम 'द मैन बिहाइंड द वर्डिक्ट' में संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने उज्ज्वल निकम का स्वागत करते हुए कहा कि उनके जैसी प्रतिष्ठित कानूनी शख्सियत का मध्य प्रदेश आना सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री ने आतंकवाद से जुड़े महत्वपूर्ण मुकदमों में निकम के योगदान की सराहना की और उनके जीवन एवं कानूनी सफर पर आधारित फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस आयोजन के लिए संस्था सार्थक और आयोजक दीपक जैन 'टीनू' के प्रयासों की भी प्रशंसा की।

अपने संबोधन में उज्ज्वल निकम ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुकदमे से जुड़े अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह उनके जीवन की महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी यात्रा रही है। इस मुकदमे ने उन्हें सत्य और न्याय के लिए दृढ़ता से खड़े रहने का संकल्प और मजबूत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष केवल सुरक्षा बलों तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून के शासन और न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में मुंबई आतंकी हमले के शहीदों और निर्दोष पीड़ितों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई।

न्यायपालिका की भूमिका पर अपनी बात रखते हुए निकम ने कहा कि न्यायपालिका को भी अपने अधिकारों के दायरे में रहते हुए अतिरिक्त टिप्पणियां करने से बचना चाहिए, विशेषकर ऐसी टिप्पणियों से जो आवश्यक न हों। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में तथ्यों, साक्ष्यों और कानून के आधार पर निर्णय लेने के महत्व को रेखांकित किया।

अपनी जिंदगी और पेशेवर सफर पर आधारित फिल्म 'प्रहार – द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वे इंदौर फिल्म का प्रचार करने नहीं, बल्कि एक सार्थक संवाद के लिए आए हैं। उनके अनुसार, किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित फिल्म केवल घटनाओं का चित्रण नहीं होती, बल्कि उसके पीछे मौजूद संघर्ष, निर्णय, विचार और अनुभवों को समझने का अवसर भी देती है। फिल्म में अभिनेता राजकुमार राव ने उज्ज्वल निकम की भूमिका निभाई है। फिल्म की निर्धारित रिलीज से एक दिन पहले आयोजित इस कार्यक्रम में उनके वास्तविक जीवन और पेशेवर यात्रा पर चर्चा हुई।

निकम ने अपने शुरुआती जीवन का एक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि वे पहले डॉक्टर बनना चाहते थे और उनके पिता की भी यही इच्छा थी। उस समय वे वकालत के पेशे में आने को लेकर उत्साहित नहीं थे, लेकिन जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों ने उन्हें कानून के क्षेत्र की ओर अग्रसर किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और काम के प्रति ईमानदारी जैसे संस्कार उन्हें परिवार से मिले, जिन्होंने उनके पेशेवर जीवन को दिशा दी। उनके व्यक्तिगत अनुभवों ने कार्यक्रम को आत्मीयता प्रदान की और उपस्थित युवाओं को उनके जीवन के अनछुए पहलुओं से परिचित कराया।

कार्यक्रम में उज्ज्वल निकम की धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति निकम भी उपस्थित रहीं। अपर महाधिवक्ता राहुल सेठी, सोनल गुप्ता और आयोजक दीपक जैन 'टीनू' ने मां अहिल्या की प्रतिमा, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इंदौर की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में मां अहिल्या की प्रतिमा भेंट कर उनका सम्मान किया गया। स्टेट बार एसोसिएशन की ओर से राकेश भदौरिया, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पाल और शासकीय अधिवक्ता अभिजीत सिंह राठौर ने भी उनका स्वागत किया। श्रीमती ज्योति निकम का स्वागत श्रीमती अर्चना खेर और उप महाधिवक्ता कुशल गोयल ने किया।

आयोजन में सांसद शंकर लालवानी, जीतू जिराती, गोलू शुक्ला, पद्मश्री भालू मोंढे, डॉ. राजीव चौधरी, प्रकाश जैन सहित न्याय जगत की प्रमुख हस्तियां, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की सहभागिता ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की।

कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' प्रस्तुत किया गया। आयोजक दीपक जैन 'टीनू' ने स्वागत उद्बोधन दिया और कार्यक्रम के उद्देश्य एवं पृष्ठभूमि से अवगत कराया। उज्ज्वल निकम के जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों और राष्ट्र के प्रति योगदान का परिचय भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संयुक्त संचालन उप महाधिवक्ता श्रेयराज सक्सेना और शासकीय अधिवक्ता दृष्टि रावल ने किया।

कार्यक्रम के अंतिम चरण में आयोजन समिति के सदस्यों राज्यवर्धन गावड़े, पीयूष पाराशर, तेजस जैन, हर्ष मेहता, रोहित जैन, गोविंद सिंह बैस, भूपेंद्र कुशवाह, आकाश शर्मा, कमलेश जोशी, अनिमेष परमार, नितेश मुछाल, पंकज जैन, अमित सोनी, धवल जैन, अंकित रावल और गौरव नाहर ने बड़ी पुष्पमाला पहनाकर उज्ज्वल निकम का सामूहिक अभिनंदन किया। अंत में हर्ष मेहता ने अतिथियों, सहयोगियों, आयोजन समिति और उपस्थित जनसमुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया।

संस्था सार्थक के नेतृत्व में आयोजित 'द मैन बिहाइंड द वर्डिक्ट' कानून, न्याय, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रहित जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाने की पहल के रूप में सामने आया। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे प्रेरक व्यक्तित्वों के अनुभवों को समाज और नई पीढ़ी तक पहुंचाना रहा, जिनका जीवन संघर्ष, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल प्रस्तुत करता है।

इंदौर विकास प्राधिकरण के नव नियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप केरकट्टा ने पदभार ग्रहण किया

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर विकास प्राधिकरण के नव नियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप केरकट्टा ने गुरुवार 15 अक्टूबर को पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

पदभार ग्रहण करने के पश्चात श्री केरकट्टा ने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रेजेंटेशन देखा तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण के कार्यों और विभागीय व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। उल्लेखनीय है कि श्री संदीप केरकट्टा इसके पूर्व भोपाल विकास प्राधिकरण में भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

मंत्री श्री सिलावट ने बायपास एमआर-10 जंक्शन फ्लायओवर का अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने शुक्रवार को बायपास के बेस्ट प्राइज एमआर-10 थ्री लेयर जंक्शन फ्लायओवर का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री प्रवीण यादव एवं संबंधित अधिकारी साथ थे। मंत्री श्री सिलावट ने बायपास एमआर-10 जंक्शन फ्लायओवर के शेष कार्यों के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि फ्लायओवर की रोड मार्किंग सहित डिवाइडर और सेंट्रल लाईटिंग का कार्य आगामी 30 दिन में पूरा किया जाये। आवश्यकता होने पर संसाधनों और मेन पॉवर की संख्या बढ़ाई जाये। उन्होंने मौके पर ही निगम अधिकारियों से मोबाइल पर संपर्क कर फ्लायओवर के नीचे पाइप लाइन को बदलने के निर्देश दिये। साथ ही बेस्ट प्राइज के सामने बोगदे से झलारिया की ओर जाने वाले मार्ग को 30 दिन में पूरा करने के निर्देश दिये। साथ ही एमपीईबी के उच्च अधिकारियों से सेंट्रल लाईटिंग को निश्चित समय-सीमा पूर्ण करने के लिये चर्चा की।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि बायपास एमआर-10 जंक्शन की दोनों लेन शुरू होने से करीब डेढ़ लाख से अधिक वाहन चालकों को यातायात में सुगमता मिलना शुरू हो गई है। आगामी त्यौहारों को देखते हुए आम नागरिकों को भी आवाजाही में राहत मिलेगी। साथ ही बोगदे के नीचे से स्थाई यातायात शुरू हो जाने के बाद करीब 100 कॉलोनियों के रहवासियों का आवागमन शुरू हो सकेगा। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि फ्लायओवर की मुख्य केरेज वे और सर्विस रोड शुरू हो जाने के बाद इस क्षेत्र में यातायात बाधित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह इंदौर का प्रवेश द्वार है इसलिये इस क्षेत्र का बेहतर तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाये। इस क्षेत्र में तीन बड़े शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी यातायात में सुगमता मिलेगी। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति और विकास के पद पर अग्रसर है। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश में तेजी से सड़क, फ्लायओवर का निर्माण हो रहा है। मंत्री श्री सिलावट ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। एनएचएआई द्वारा बताया गया कि करीब 77 करोड़ रूपये की लागत से 1.8 किलो मीटर लम्बा और 180 मीटर चौड़ा बायपास एमआर-10 जंक्शन फ्लायओवर के बन जाने के बाद आवासीय कॉलोनी के रहवासियों को भी राहत मिलेगी। मंत्री श्री सिलावट ने एमआर-10 थ्री लेयर जंक्शन फ्लायओवर की बोगदे और केरेज वे का भी निरीक्षण किया।

भाजपा में गुटबाजी : इंदौर में जलसंकट को लेकर मंत्री ने बुलाई बैठक, सिर्फ तीन ही विधायक पहुंचे

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा जलसंकट की रोकथाम और प्रबंधन को लेकर गुरुवार को बुलाई गई बैठक में सिर्फ तीन विधायक ही पहुंचे। बैठक के बाद जब विजयवर्गीय से विधायकों की बैठक से दूरी की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जो नहीं आए हैं उनके यहां जलसंकट नहीं होगा।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव के अलावा बैठक में शामिल होने वालों में विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया और मधु वर्मा शामिल थे। विधायकों की बैठक से दूरी ने एक बार फिर भाजपा की गुटबाजी उजागर कर दी। कांग्रेस ने भी इस मामले में भाजपा पर निशाना साधा है।

जागरुकता अभियान चलाना होगा - बैठक सुबह 10 बजे शुरू होना थी, लेकिन यह करीब डेढ घंटे देरी से शुरू हुई। महापौर परिषद के सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर विजयवर्गीय ने कहा कि हमें जलसंकट की आहट सुनाई दे रही है। इससे निपटने के लिए जागरुकता अभियान चलाना होगा।

उपलब्ध पानी का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें-इस साल बोरिंग सूखने की आशंका है। जिन क्षेत्रों में नर्मदा लाइन नहीं है वहां पानी कैसे पहुंचाया जाए, यह बड़ा सवाल है। शावर की बजाय बाल्टी में पानी भरकर स्नान करें। आरओ के वेस्ट वाटर का उपयोग घर की साफ-सफाई में करें अर्थात हमारे पास उपलब्ध पानी का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें।

अगर कोई पाइप लगाकर कार धोए तो उसका तत्काल चालान बनाया जाए। विजयवर्गीय ने कहा कि महापौर ने जलसंकट से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपये मांगे हैं। हम जरूरत पडने पर 100 करोड़ रुपये भी देंगे।

जागरूकता अभियान चलाएंगे-इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अल्पवर्षा की स्थिति में बारिश का दौर खत्म होने के साथ ही इंदौर नगर निगम ने भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। हर वार्ड का मास्टर प्लान, संकट में सभी तक पानी पहुंचे इसकी तैयारी इसको लेकर जागरुकता का काम हम शुरू कर चुके हैं।

ये भी हुए थे शामिल- बैठक में जनकार्य समिति अध्यक्ष राजेंद्र राठौर, जलकार्य समिति अभिषेक बबलू शर्मा, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल, नगरीय प्रशासन एवं विकास कमिश्नर संकेत भोंडवे आदि शामिल हुए।

इन विचारों पर हुआ मंथन- अवैध से वैध नल कनेक्शन के लिए आउटसोर्स टीम के साथ सर्वे कराया जाए, डोर टू डोर नल कनेक्शन का सर्वे कराया जाए, नवीन नल कनेक्शन के दस्तावेजो का सरलीकरण किया जाए, बोरिंग की जानकारी निकाली जाए, किनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है पता लगाया जाए, जल संकट के संबंध में मेयर इन कौंसिल की बैठक बुलाई जाए, जिन नलों पर टोटी नहीं है उनके जल कनेक्शन काटे जाए, पानी चोरी करने वालो के विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए प्रविधान किए जाएं, पानी के लिये आपातकाल घोषित करें, नर्मदा जल से कार व वाहन धोने वालो पर कार्यवाही करें, तालाबों के आसपास 8 इंच के बोरिंग कराकर हाइड्रेंट बनाए जाएं

कांग्रेस ने साधा निशाना- आने वाले जल संकट के समाधान के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा आयोजित बैठक में विधायकों के नहीं पहुंचने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि भाजपा की आंतरिक गुटबाजी शहर के मुद्दों पर भी हावी हो रही है।

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया ने कहा कि जिले में भाजपा के नौ विधायक और इनमें दो मंत्री हैं। बैठक एक मंत्री ने बुलाई और उनके समेत सिर्फ चार विधायक बैठक में पहुंचे। पांच विधायकों की गैरमौजूदगी बता रही है कि भाजपा को शहर की और यहां के नागरिकों की कोई चिंता नहीं है।

जब भाजपा के विधायक शहर के लिए आपसी गुटबाजी को भी नहीं भूल सकते तो भला वे जनता का भला कैसे सोच सकते हैं? कांग्रेस की ओर से कहा गया कि भाजपा नेताओं को शहर की चिंता है तो सबसे पहले इंदौर को सूखाग्रस्त घोषित करवाएं। अपनी सरकार से अतिरिक्त फंड और किसानों को राहत राशि का आवंटन करवाएं।

बड़ा गणपति से बिजासन माता मंदिर तक 18 अक्टूबर को निकलेगी विशाल चुनरी यात्रा, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक एयरपोर्ट रोड पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना

पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता की नागरिकों से अपील, वैकल्पिक मार्गों का करें उपयोग

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में रविवार, 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से बड़ा गणपति मंदिर से बिजासन माता मंदिर तक विशाल चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। भाजपा के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने नागरिकों से यात्रा में शामिल होकर माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नागरिकों से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक एयरपोर्ट रोड पर जाने से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है।

चुनरी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। यात्रा बड़ा गणपति मंदिर से प्रारंभ होकर बिजासन माता मंदिर तक पहुंचेगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता को देखते हुए एयरपोर्ट रोड पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। ऐसे में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाएं।

पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के अनुसार, एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए छोटा बांगड़दा से सुपर कॉरिडोर होते हुए एयरपोर्ट पहुंचने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। एयरपोर्ट रोड के चार लेन वाले हिस्से में से दो लेन पर चुनरी यात्रा निकलेगी, जबकि शेष दो लेन पर यातायात जारी रखने की व्यवस्था रहेगी।

एयरपोर्ट रोड के समानांतर पल्हर नगर मार्ग (60 फीट रोड), छोटा बांगड़दा मार्ग और सुपर कॉरिडोर का उपयोग भी किया जा सकेगा। भंवरकुआं, अन्नपूर्णा और महू नाका की ओर से एयरपोर्ट जाने वाले नागरिक चंदन नगर, सिरपुर, जवाहर टेकरी, चोइथराम हॉस्पिटल चौराहा, नावदा, ग्राम रिजलाय और हिंकारगिरी होते हुए एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं।

नागरिकों से अपील की गई है कि वे रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक एयरपोर्ट रोड की ओर जाने से यथासंभव बचें। विशेष रूप से विमान से यात्रा करने वाले लोग पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

चुनरी यात्रा के आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सामूहिक रूप से माता की आराधना और धार्मिक आस्था से जोड़ना है। आयोजकों ने शहरवासियों से यात्रा में सहभागिता करने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का भी आग्रह किया है।

निवर्तमान राज्यपाल थावरचंद गहलोत का इंदौर आगमन पर आत्मीय स्वागत, कैलाश विजयवर्गीय बोले– बेदाग रहा है उनका राजनीतिक जीवन

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत शुक्रवार को विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। इंदौर विमानतल पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया। ढोल-ढमाकों के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाएं पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

इंदौर पहुंचने पर मीडिया से चर्चा करते हुए थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक में अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के रूप में उन्होंने सभी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने और सबको साथ लेकर कर्नाटक के विकास में योगदान देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने कार्यकाल को संतोषजनक बताते हुए कहा कि भविष्य में पार्टी उन्हें जो भी दायित्व सौंपेगी, उसका वे पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने थावरचंद गहलोत के राजनीतिक जीवन और कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि संगठन ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया। वे ऐसे नेताओं में शामिल हैं, जिनका राजनीतिक जीवन बेदाग रहा है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका अनुभव और कार्य के प्रति समर्पण राजनीतिक एवं संगठनात्मक जीवन में प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर विधायक अरुण भीमावत, घनश्याम काकणी, सतीश मालवीय, बलजीत सिंह चौहान, प्रदीप शर्मा, अभिनव शर्मा, चंद्रशेखर मालवीय और राजेश दुभरिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने विमानतल पर गहलोत की अगवानी कर उनका स्वागत किया और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

थावरचंद गहलोत के इंदौर आगमन पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। ढोल-ढमाकों और पुष्पमालाओं के साथ किए गए स्वागत ने आयोजन को आत्मीयता और उत्साह से भर दिया।

इंदौर में बीएससी का छात्र बेच रहा था म्यूल अकाउंट, कमीशन के झगड़े में साथी सहित गिरफ्तार

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों की खरीद-फरोख्त में बीएससी का एक छात्र शामिल मिला है। तुकोगंज पुलिस ने ऐसे ही नेटवर्क से जुड़े दो युवकों को पकड़ा है।

पुलिस के मुताबिक, छात्र आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रुपये का लालच देकर उनके बैंक खाते खरीदता और आगे साइबर अपराधियों तक पहुंचाता था। एक खाते पर दो हजार रुपये का मुनाफा कमाने वाले दोनों के बीच कमीशन को लेकर विवाद हो गया। इसी झगड़े ने पुलिस को म्यूल अकाउंट के कारोबार तक पहुंचा दिया।

दो युवकों के बीच विवाद की सूचना मिली थी - तुकोगंज पुलिस के अनुसार, बुधवार को एमजी रोड स्थित ट्रेजर आइलैंड मॉल के सामने दो युवकों के बीच विवाद की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे प्रधान आरक्षक भागचंद्र और मनीष राजावत ने हिमांशु शर्मा निवासी खनियाधाना, शिवपुरी और आर्यन साहू निवासी कमला नेहरू कॉलोनी, खड़े गणपति को पकड़ा।

पूछताछ में बैंक खातों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया। हिमांशु बीएससी का छात्र है और साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराता था। बुधवार को वह आर्यन के कहने पर तीन खातों से संबंधित दस्तावेज लेकर आया था। इसी दौरान कमीशन को लेकर दोनों में विवाद हो गया।

अब तक 20 से अधिक बैंक खाते सप्लाई कर चुका है-पूछताछ में हिमांशु ने बताया कि वह अब तक 20 से अधिक बैंक खाते सप्लाई कर चुका है। वह लोगों से एक खाता 14 हजार रुपये में खरीदता और आर्यन को 16 हजार रुपये में देता था। इस तरह हर खाते पर दो हजार रुपये का अंतर रहता था। पुलिस अब इन खातों का इस्तेमाल किन साइबर अपराधों में हुआ, इसकी जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, आर्यन ने पूछताछ में स्कीम नंबर 51 में रहने वाले आदर्श रघुवंशी से संपर्क होने की जानकारी दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, गिरोह टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क और लेन-देन का नेटवर्क चला रहा था।

इंदौर में लापरवाही की इंतेहा : प्रसव के बाद महिला की कोख में छोड़ा कपड़ा, 5 महीने बाद निकला

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर के वी-वॉन अस्पताल में प्रसव के दौरान कथित चिकित्सकीय लापरवाही का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया है कि डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में सर्जिकल माप (कपड़ा) छोड़ दिया गया, जिसके कारण उसे करीब छह माह तक असहनीय दर्द और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

बाद में दूसरे अस्पताल में जांच और ऑपरेशन के दौरान पेट से मॉप निकाला गया। महिला ने मामले में अस्पताल प्रबंधन और डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर दीपा जोशी के खिलाफ सीएमएचओ कार्यालय में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है।

महिला चिकित्सक सरकारी डॉक्टर हैं- शिकायत इसीलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि प्रसव कराने वाली महिला चिकित्सक सरकारी डॉक्टर हैं और वर्तमान में एमटीएच अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रही हैं। ऐसे में एमटीएच अस्पताल के बजाय प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराना कई सवाल खड़े कर रहा है।

अवैध नंबर प्लेट और हूटर के विरुद्ध परिवहन विभाग की कार्रवाई

तेजाजी नगर चौराहे पर करीब 100 वाहनों की जांच, 33 वाहनों के चालान कर 18 हजार रुपये का राजस्व वसूला

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार यातायात नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा तेजाजी नगर चौराहे पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों, शीशों पर प्रतिबंधित काली फिल्म लगाने वाले वाहनों तथा नंबर प्लेट पर धार्मिक प्रतीक, अनधिकृत नाम एवं अन्य अवैध प्लेटों का उपयोग करने वाले वाहनों की जांच की गई। इस दौरान करीब 100 वाहनों की जांच की गई, जिनमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 33 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 18 हजार रुपये का राजस्व वसूल किया गया।

अभियान के दौरान कुछ प्रशासनिक एवं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों, धार्मिक नेताओं, उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं तथा पत्रकारों द्वारा कार्रवाई को प्रभावित करने और रोकने के लिए दबाव बनाने के प्रयास किए गए। इसके बावजूद परिवहन विभाग की टीम ने बिना किसी दबाव में आए निष्पक्षता एवं दृढ़ता के साथ नियमानुसार कार्रवाई जारी रखी।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि यातायात नियम सभी के लिए समान हैं। किसी भी व्यक्ति के पद, प्रभाव अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और वाहन संबंधी नियमों के पालन के लिए विभाग द्वारा इस प्रकार के जांच अभियान निरंतर जारी रखे जाएंगे।

यह कार्रवाई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) श्री राजेश गुप्ता एवं परिवहन निरीक्षक श्री आकाश सिटोले द्वारा की गई।

आक्याबिका में जन संवाद, 53 आवेदनों का मौके पर निराकरण, अभियान सफलता की ओर-कलेक्टर

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को विकासखंड मल्हारगढ़ के ग्राम आक्याबिका में जन संवाद आयोजित हुआ। कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। मौके पर ही 53 आवेदनों का निराकरण किया गया। जन संवाद में कुल 127 आवेदन प्राप्त हुए थे। जन संवाद में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाए। जिन आवेदनों का तत्काल निराकरण संभव नहीं है, उनमें समय-सीमा तय की जाए।

कलेक्टर ने कहा कि मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान सफलता अर्जित कर रहा है। अधिकारी अभियान की भावना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। पिछले ढाई महीने में ढाई हजार शिकायतों का निराकरण किया गया है। विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों में मंदसौर जिला प्रदेश के टॉप-5 जिलों में शामिल है। जिन ग्रामों में अधिक समस्याएं मिलीं, वहां विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में कलेक्टर ने ग्राम पहेड़ा में नगर पालिका के जलापूर्ति केंद्र का निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम कचनारा में जीवन सिंह ठाकुर के गोट फार्म को देखा। फार्म में उन्नत नस्ल के बकरे-बकरियों, गोवंश और मुर्गी पालन किया जा रहा है। कलेक्टर ने गतिविधियों की सराहना करते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेने को कहा। जीवन सिंह ठाकुर को राष्ट्रीय पशुधन एवं डेयरी विकास निगम से 81 लाख रुपये का वित्त पोषण ऋण के रूप में मिला है। उनके फार्म में 525 सिरोही नस्ल की बकरियां हैं। इसके अलावा वे कड़कनाथ मुर्गी और गिर क्रॉस नस्ल की गायों का पालन भी कर रहे हैं। वे प्रतिमाह 65 हजार रुपये बैंक किस्त अदा कर रहे हैं। बकरी पालन से उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख और मुर्गी पालन से एक से डेढ़ लाख रुपये की आय हो रही है। अभियान के तहत ग्राम बरुजना में कंवरलाल मेघवाल और मोहिनी बाई के प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों का निरीक्षण किया गया। योजना में प्रत्येक हितग्राही को 1 लाख 20 हजार रुपये तथा मनरेगा से मजदूरी के रूप में 15 हजार रुपये मिलते हैं।

टकरावद में स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल का भ्रमण- ग्राम टकरावद में शासकीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं, औषधियों और उपकरणों की उपलब्धता का जायजा लिया और बेहतर चिकित्सा के निर्देश दिए। इसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों से संवाद किया। कलेक्टर ने बच्चों को जीवन में कुछ हटकर सोचने और लाइफ स्किल डेवलपमेंट के टिप्स दिए। स्कूल परिसर में बालिकाओं करिश्मा प्रजापत और सिमरन ने पूछा कि आईएएस कैसे बनते हैं। इस पर कलेक्टर ने कहा कि अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें शत-प्रतिशत दें। स्नातक के बाद कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण से तैयारी में जुट जाएं और हमेशा सकारात्मक रवैया रखें। इसके बाद कलेक्टर ने प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन किया और उसकी गुणवत्ता परखी। ग्राम चौबीसा मगरा की गौशाला में गौपूजन कर गोवंश को आहार खिलाया।

अमानक उर्वरक के मामले में कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

प्रयोगशाला जांच में उर्वरक अमानक पाए जाने पर कृषि विभाग की शिकायत पर कार्रवाई

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में अमानक उर्वरक के विक्रय के मामले में कृषि विभाग की शिकायत पर थाना मनासा में मेसर्स महाधन एग्रीटेक लिमिटेड के जिम्मेदार व्यक्ति प्रतीक हर्षद भाई पटेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 19, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराओं 3 एवं 7 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 318(4), 274 एवं 275 के तहत कार्रवाई की गई है।

प्राथमिकी के अनुसार, 23 अगस्त 2024 को ग्राम कंजार्डा स्थित वैभव एंटरप्राइजेज के निरीक्षण के दौरान 20-20-0-13 उर्वरक का वैधानिक नमूना लिया गया था। नमूने की प्रयोगशाला जांच एवं रेफरी विश्लेषण की अंतिम रिपोर्ट में उर्वरक अमानक पाया गया। इसके बाद कृषि विभाग द्वारा मामले में वैधानिक कार्रवाई करते हुए संबंधित कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई।

अमानक कृषि आदान के विक्रय पर होगी सख्त कार्रवाई- कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। जिले में यदि किसी भी विक्रेता द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले उर्वरक या बीज का विक्रय किया जाता है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अमानक उत्पाद की आपूर्ति करने वाली संबंधित कंपनी एवं उसके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृषि विभाग द्वारा उर्वरक एवं बीज की गुणवत्ता की जांच तथा विक्रय व्यवस्था की निगरानी निरंतर की जा रही है।

सिंगोली में अन्नदाताओं के पट्टों पर कॉर्पोरेट की गिद्ध दृष्टि कतई बर्दाश्त नहीं- समंदर पटेल

सिंगोली/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जावद विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, कद्दावर जननायक एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी समंदर पटेल ने सिंगोली क्षेत्र के ग्राम फुसरिया, धारडी, थड़ौद और आसपास के ग्रामीण अंचलों में सौर ऊर्जा प्लांट की आड़ में गरीब, भूमिहीन और शोषित किसानों की पट्टा जमीनों को हड़पने की कॉरपोरेट साजिश के खिलाफ पूरी ताकत से हुंकार भर दी है। जोधपुर की निजी कंपनी अवादा एमपी सोलर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिला 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबों को जीविकोपार्जन के लिए आवंटित शासकीय पट्टों पर 1 साल के शॉर्ट-टर्म एग्रीमेंट (इकरारनामे) की आड़ में किए जा रहे कथित अवैध कब्जे के खेल पर समंदर पटेल ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश की भाजपा सरकार, स्थानीय राजस्व प्रशासन और क्षेत्र के पांच बार के विधायक को कटघरे में खड़ा करते हुए अन्नदाताओं के हक की लड़ाई को सिंगोली से लेकर जिला मुख्यालय तक सड़कों पर लड़ने का ऐतिहासिक एलान कर दिया है।

प्रभावित गांवों का दौरा कर पीड़ित अन्नदाताओं और ग्रामीणों का दर्द जानने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता समंदर पटेल ने एक अत्यंत गंभीर और दूरगामी नीतिगत बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार एक तरफ इस वर्ष को किसान वर्ष घोषित कर खेतों में सूक्ष्म दाब सिंचाई प्रणाली जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू करने के कागजी दावे कर रही है, लेकिन जावद की जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट और भयावह है। जावद के सिंगोली क्षेत्र में रसूखदार कॉर्पोरेट कंपनियां गरीब पट्टाधारक किसानों की उपजाऊ जमीनें निगलने की बड़ी साजिश रच रही हैं। राजस्व नियमों के अनुसार शासकीय पट्टे पूरी तरह से अहस्तान्तरणीय होते हैं और इनकी खरीद-फरोख्त या हस्तांतरण कानूनन प्रतिबंधित है।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत रतनगढ़ में समाधान शिविर संपन्न

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जावद विकासखंड की रतनगढ़ तहसील में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विधायक श्री ओमप्रकाश सखलेचा एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमन वैष्णव ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विधायक श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शासन एवं प्रशासन को आमजन के निकट लाने की महत्वपूर्ण पहल है। शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो। उन्होंने अधिकारियों को शिविर में प्राप्त आवेदनों का सात दिवस में निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही, आगामी शिविर में पूर्व में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा करने की बात कही।

ग्रामीण विकास एवं रोजगार पर विशेष जोर- विधायक श्री सखलेचा ने ड्रोन सर्वे से संबंधित आवेदनों का निराकरण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल सके।

सीमांकन, पेंशन, फसल बीमा सहित विभिन्न समस्याओं के आवेदन प्राप्त-समाधान शिविर में ग्रामीणों ने सीमांकन, सीमा विवाद, पेंशन, फसल बीमा, आंगनवाड़ी, विद्यालय एवं सड़क संबंधी समस्याओं से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। विधायक एवं अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मप्रविम पत्रोंपाधि अभियंता संघ मंदसौर वृत्त ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मंदसौर वृत्त द्वारा मप्रविम पत्रोंपाधि अभियंता संघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगो को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन और माननीय प्रमुख सचिव महोदय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन के नाम माननीय कलेक्टर महोदय मंदसौर के माध्यम से ज्ञापन सौपा गया। जिसमे वृत्त अध्यक्ष रॉबिन साहू, वृत्त सचिव सुनील सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष राकेश उपमन्यु, महेश कुमावत, एन के प्रजापति, सीके जैन, एल के शर्मा, महतो, विवेक मिश्रा आदि उपस्थित रहे। ज्ञापन में मांग कि गई है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों (पूर्व, मध्य, पश्चिम क्षेत्र), विद्युत उत्पादन कंपनी एवं विद्युत पारेषण कंपनी में मैदानी स्तर पर 24 घंटे विद्युत आपूर्तिसुचारू रखने वाले कनिष्ठ यंत्री तथा पदोन्नत सहायक यंत्री संवर्गका प्रतिनिधित्व करता है । अत्यंत विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमित संसाधनों के बावजूद हमारे अभियंता संवर्गद्वारा निरंतर राजस्व वसूली, लाइन हानियों में कमी एवं प्रदेशवासियों को निर्बाध व गुणवत्तापूर्णविद्युत आपूर्तिसुनिश्चित की जा रही है। इसके उपरांत भी लंबे समय से इस संवर्गकी वर्षोंसे लंबित सेवा संबंधी विसंगतियों एवं पदोन्नति के अवसरों की कमी का निराकरण नहीं होने से अभियंताओं में गहरा असंतोष एवं निराशा व्याप्त है। ज्ञापन में बताया गया हैं कि सभी पदोन्नत सहायक यंत्रियों को नियमों को शिथिल करते हुए आगामी डीपीसी में कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नतिप्रदान की जावे। इसके साथ ही ऊर्जाविभाग द्वारा समस्त विद्युत कंपनियों के प्रबंध संचालक को प्रेषित संगठनात्मक संरचना से संबंधित पत्र क्रमांक 4992-93/13/2011 दिनांक 09 जून 2011 भोपाल की कंडिका क्रमांक- 2 तथा वर्तमान संगठनात्मक संरचना में पूर्ववर्तीविद्युत मंडल द्वारा कंपनियों में अंतरित कार्मिकों के लिए पदोन्नतिहेतु आरक्षित किए गए पदों को पूर्णतः यथावत रखा जावे एवं किसी भी अन्य संगठन की मांग पर इसे किसी भी परिस्थिति में निरस्त/संशोधित न किया जावे। जूनियर इंजीनियर संवर्गको संपूर्ण सेवाकाल में न्यूनतम 3 पदोन्नतियां सुनिश्चित करने हेतु कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षण यंत्री के 50 प्रतिशत रिक्त पदों को पदोन्नत सहायक अभियंता वर्गसे भरा जावे। सहायक यंत्री की सीधी नवीन भर्तीपर तत्काल प्रभाव से रोक लगाईजावे तथा सभी रिक्तियों को कनिष्ठ यंत्रियों की पदोन्नतिसे भरा जावे। चतुर्थउच्च वेतनमान की स्वीकृतिहेतु अव्यावहारिक कंडिका 11 को तत्काल विलोपित किया जावे तथा पात्रता अवधिकी गणना कनिष्ठ यंत्री पद के स्थान पर मंडल / कंपनी मेंप्रथम नियुक्तितिथिसे की जावे। वर्ष 2018 के पश्चात नियुक्त कनिष्ठ यंत्रियों की वेतन विसंगतिदूर कर उनका वेतनमान एवं ग्रेड-पे पूर्ववर्ती अभियंताओं के समान किया जावे, आदि मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।

सुवासरा में अघोषित बिजली कटौती पर कांग्रेस का धरना, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सुवासरा क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और खाद वितरण में आ रही समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पुराना बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान सभी वक्ताओं और नेताओं का संबोधन हुआ, जिसके बाद सभी कांग्रेस जन केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पैदल रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार सुनील पिडियार को ज्ञापन सौंपा गया। ?धरने को संबोधित करते हुए मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार दूसरे राज्यों को बिजली बेच रही है, जबकि मंदसौर जिले में रात-रात भर अघोषित कटौती हो रही है। उन्होंने अखबार में छपी तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक हरदीप सिंह डंग बिजली कंपनी के अफसरों के साथ बैठकर कटौती तय कर रहे हैं, जिससे साफ है कि इन्हें किसान और गरीब की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कटौती बंद नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ईवीएम में हेराफेरी, खाद की किल्लत, खाद्य मिलावट और तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठाए।

कांग्रेस नेता राकेश पाटीदार ने कहा कि कांग्रेस राज में 100-200 रुपये बिजली बिल आता था, आज भाजपा राज में 1500 से 2500 रुपये आ रहा है और घर के मीटर राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ रहे हैं। सरकार विधानसभा में बिजली सरप्लस होने और दूसरे राज्यों को बेचने की बात कहती है, लेकिन किसानों को लोड शेडिंग के नाम पर कटौती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-टोकन लाकर खाद की कालाबाजारी शुरू कर दी गई है जिससे किसानों को दोगुने दाम पर खाद लेना पड़ रहा है। पाटीदार ने चेतावनी दी कि यदि अघोषित कटौती बंद नहीं हुई तो एमपीईबी और तहसील कार्यालय पर ताला लगाया जाएगा। रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसियों ने तहसीलदार सुनील पिडियार को जो ज्ञापन सौंपा, उसमें बताया गया कि सुवासरा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा कई दिनों से अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है जिससे रहवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि रबी फसल बोआई और नवरात्रि पर्व को देखते हुए रात्रि के समय बिजली देने के बजाय दिन के समय पर्याप्त बिजली दी जाए और खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द उचित विद्युत व्यवस्था नहीं की गई तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व ग्रामीणजनों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदेही शासन-प्रशासन की रहेगी। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल जैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे।

अनंत शक्ति और सिद्धि का खजाना है शतावधान, शिक्षा प्रणाली में इसे लागू करने पर हो चर्चा

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कल रात आपने क्या खाया था, यह भी कई बार तुरंत याद नहीं आता, लेकिन शतावधानी व्यक्ति एक साथ सैकड़ों गतिविधियों को याद रखकर अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति का परिचय देता है। यह मन और बुद्धि की एकाग्रता का परिणाम है। उक्त विचार बही तीर्थ पेढ़ी के अध्यक्ष अशोक कुमठ ने प्रतापगढ़ में आयोजित पंच शतावधान कार्यक्रम में 'शिक्षा प्रणाली में शतावधान लागू हो' विषय पर चर्चा के दौरान व्यक्त किए।

कुमठ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति और सिद्धि का खजाना छिपा हुआ है। एकाग्र मन और निरंतर साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति को असाधारण स्तर तक विकसित कर सकता है। शतावधान इसी एकाग्रता और अभ्यास का उदाहरण है, जिसमें व्यक्ति एक साथ अनेक विषयों, वस्तुओं और गतिविधियों को याद रखने की क्षमता प्रदर्शित करता है। प्राचीन भारतीय परंपरा में ऋषि-मुनियों द्वारा भी इस प्रकार के प्रयोग किए जाते थे। यह परंपरा भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान और साधना को संरक्षित रखने की प्रेरणा देती है। आयोजन के सूत्रधार राकेश मारवाड़ी ने बताया कि जैन साध्वी जिनप्रियाश्री ने 500 अवधान का सफल प्रयोग कर इतिहास रचा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 11 बजे मंडी प्रांगण में हुआ। संचालन संवेगभाई सूरत ने किया। लाभार्थी सालगिया गोल्ड परिवार प्रतापगढ़ सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे।

पोष दशमी पर आराधना के लिए निश्रा की स्वीकृति- बही तीर्थ के अध्यक्ष अशोक कुमठ ने बताया बही ट्रस्ट मंडल ने साध्वी मृदुप्रियाश्री से आगामी पोष दशमी पर आयोजित अनुमोदना-तप आराधना में निश्रा प्रदान करने की विनती की। साध्वीश्री ने इस विनती को स्वीकार कर स्वीकृति प्रदान की।

अमानक उर्वरक के मामले में कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में अमानक उर्वरक के विक्रय के मामले में कृषि विभाग की शिकायत पर थाना मनासा में मेसर्स महाधन एग्रीटेक लिमिटेड के जिम्मेदार व्यक्ति प्रतीक हर्षद भाई पटेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 19, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराओं 3 एवं 7 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 318(4), 274 एवं 275 के तहत कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी के अनुसार, 23 अगस्त 2024 को ग्राम कंजार्डा स्थित वैभव एंटरप्राइजेज के निरीक्षण के दौरान 20-20-0-13 उर्वरक का वैधानिक नमूना लिया गया था। नमूने की प्रयोगशाला जांच एवं रेफरी विश्लेषण की अंतिम रिपोर्ट में उर्वरक अमानक पाया गया। इसके बाद कृषि विभाग द्वारा मामले में वैधानिक कार्रवाई करते हुए संबंधित कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई।

अमानक कृषि आदान के विक्रय पर होगी सख्त कार्रवाई-कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। जिले में यदि किसी भी विक्रेता द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले उर्वरक या बीज का विक्रय किया जाता है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अमानक उत्पाद की आपूर्ति करने वाली संबंधित कंपनी एवं उसके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृषि विभाग द्वारा उर्वरक एवं बीज की गुणवत्ता की जांच तथा विक्रय व्यवस्था की निगरानी निरंतर की जा रही है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न

कम वर्षा को देखते हुए जल उपयोग की समुचित कार्ययोजना बनाने के निर्देश

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में इस वर्ष हुई कम वर्षा को देखते हुए उपलब्ध जल संसाधनों का नियोजित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिवाजी सागर तालाब, मालखेड़ा तालाब सहित जिले के अन्य जलाशयों में उपलब्ध जल की स्थिति, सिंचाई की आवश्यकताओं तथा जल के औद्योगिक उपयोग के संबंध में चर्चा की गई।

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने दिए निर्देश- तालाबों से अवैध पंपिंग रोकें- शिवाजी सागर, मालखेड़ा सहित जिले के सभी तालाबों में उपलब्ध जल के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित किया जाए। तालाबों से पंपिंग कर कुओं में पानी डालने और उसके माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को पानी उपलब्ध कराने के मामलों की जांच की जाए। ऐसे मामलों में संबंधित किसानों के अनुबंधों की जांच कर नियमानुसार निरस्तीकरण सहित आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अवैध पंपिंग पर विभागीय निगरानी बढ़ाएं- सभी एसडीएम, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग को अवैध पंपिंग पर पूर्णतः रोक लगाने के निर्देश दिए गए।

औद्योगिक इकाइयों के जल उपयोग का विवरण तैयार करें- जिले में पानी का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों की सूची तैयार कर उनके जल स्रोत, स्वीकृत मात्रा और निर्धारित उपयोग सीमा की जानकारी संकलित की जाए।

अवैध विद्युत कनेक्शनों पर कार्रवाई करें- अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश दिए गए कि तालाबों से अवैध पंपिंग के लिए विद्युत कनेक्शन का दुरुपयोग पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अवैध पंपिंग में प्रयुक्त अस्थायी कनेक्शनों को नियमानुसार विच्छेदित कर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसानों को अस्थायी विद्युत कनेक्शन फसल एवं सिंचाई की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही उपलब्ध कराए जाएं।

बीज एवं उर्वरक की गुणवत्ता सुनिश्चित करें- बीज और उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अमानक अथवा गलत कृषि आदानों का विक्रय नहीं किया जाए। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

नगरीय क्षेत्रों में पेयजल अपव्यय रोकें- सभी सीएमओ नगरपालिका क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था की नियमित निगरानी करें तथा लीकेज या अन्य कारणों से होने वाली पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

सांसद श्री सुधीर गुप्ता ने दिए निर्देश- जल उपयोग की प्राथमिकताएं निर्धारित करें- सांसद श्री सुधीर गुप्ता ने निर्देश दिए कि उपलब्ध जल का उपयोग सर्वप्रथम पेयजल, इसके बाद सिंचाई और तत्पश्चात औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाए।

कागजी दावों में उलझा जल जीवन मिशन, नीमच पर मंडराया 5 सालों का सबसे बड़ा पेयजल संकटः पूर्व विधायक डॉ. जाजू

विगत 5 वर्षों की तुलना में इस बार सबसे कम 685.2 मिमी बारिश

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नीमच जिले में गहराते जल संकट को लेकर पूर्व विधायक डॉ. सम्पत स्वरूप जाजू ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासनिक अनदेखी और केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आंकड़ों के साथ स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते प्रशासन और आम जनता सचेत नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में नीमच नगर सहित पूरे जिले में भीषण पेयजल संकट खड़ा हो जाएगा।

5 वर्षों में सबसे कम बारिश, मुख्य स्रोत रीते-पूर्व विधायक डॉ. जाजू ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच जिले में इस बार पिछले पाँच वर्षों में सबसे कम वर्षा दर्ज हुई है। मानसून की समय पर आमद (19 जून) होने के बावजूद अभी तक जिला औसत वर्षा के आँकड़ों से कोसों दूर है।

डॉ. जाजू ने सरकारी डेटा का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2022 में जिले में सबसे कम 797.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन इस वर्ष (2026) स्थिति और भी बदतर है, जहाँ अब तक केवल 685.2 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है। कम वर्षा के चलते नीमच शहर की जीवनदायिनी कहे जाने वाले जाजू सागर बांध और खुमानसिंह शिवाजी सागर बांध अपनी क्षमता के अनुसार नहीं भर पाए हैं।

अरबों खर्च, फिर भी धरातल पर योजना ध्वस्त-डॉ. जाजू ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन योजना जिले में पूरी तरह से तथाकथित भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ÷सरकारी कागजों के आंकड़ों में तो नीमच जिला जल जीवन योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश के शीर्ष दस प्रमुख जिलों में शुमार है, लेकिन जमीनी हकीकत जनता के सामने है। अरबों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुचारू आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी भी धरातल पर जाकर काम की गुणवत्ता और मॉनिटरिंग नहीं की, केवल बंद कमरों में समीक्षा बैठकें कर कागजी श्रेय लूटने का काम किया गया है।

नगरपालिका की एक दशक की नाकामी -नीमच शहर की पेयजल व्यवस्था पर बोलते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि नीमच नगरपालिका विगत एक दशक से नागरिकों को व्यवस्थित पानी देने में पूरी तरह नकारा साबित हुई है। पूरे शहर में दूषित जल का वितरण किया जा रहा है, जिससे बीमारियाँ फैलने का खतरा है। आए दिन शहर के किसी न किसी क्षेत्र में पाइपलाइन फूटने और हजारों लीटर पानी बहने की घटना आम हो चुकी है, जिस पर नगरपालिका का कोई नियंत्रण नहीं है।

प्रशासन बनाए एक्शन प्लान, जनता करे सहयोग-डॉ. जाजू ने जिला प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (क्काश्व) और जल संसाधन विभाग से अपेक्षा की है कि वे वर्तमान स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत अपनी कार्य योजना (एक्शन प्लान) सार्वजनिक करें ताकि जनता को पता चल सके कि भविष्य के संकट से निपटने के क्या उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से भी भावुक अपील करते हुए कहा कि वे आने वाले संकट को पहचानें, पानी की बर्बादी रोकें और स्वयं भी जल का संरक्षण करते हुए इसका सीमित व सही उपयोग करें।

सम्पादकीय

अमेरिका के लिए संकट की घड़ी

वैसे तो रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-अमेरिका-ईरान युद्ध अलग-अलग क्षेत्रों, अलग-अलग कारणों और अलग-अलग समय पर प्रारंभ हुए, परंतु जैसे-जैसे ये लंबे खिंचते जा रहे, एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। अब ये एक ही भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात का हिस्सा नजर आने लगे हैं। अनाधिकारिक रूप से ये युद्ध एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। इन्हें अब क्षेत्रीय युद्ध या संघर्ष भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन युद्धों से उत्तरी रूस से कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक प्रभावित हो चुके हैं।

रूस और ईरान ने मिलकर अमेरिका के विरुद्ध सीधे युद्ध की घोषणा भले ही न की हो, परंतु यह युद्ध दोनों आपसी सहयोग से ही लड़ रहे हैं। फरवरी 2026 में ईरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले से पहले तक ईरान सस्ते, परंतु घातक ड्रोनों की बड़े पैमाने पर रूस को आपूर्ति कर रहा था। अमेरिका से युद्ध छिड़ने पर अपनी जरूरतों के चलते हुए वह ऐसा करने में असमर्थ हो गया तो रूस ने ईरान को घातक ग्रान ड्रोनों की आपूर्ति प्रारंभ कर दी। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में जो वायु प्रतिरक्षा प्रणालियां तैनात की थीं, उनसे जूझने के लंबे अनुभव के आधार पर रूस ने इन ड्रोनों को अधिक उन्नत बनाया था, ताकि वे पश्चिमी रक्षा प्रणालियों को भेद सकें और उसका असर पिछले कई महीनों से ईरान-अमेरिका युद्ध में स्पष्ट नजर आ रहा है।

अमेरिकी तथा इजरायली वायु प्रतिरक्षा प्रणालियां ईरानी ड्रोन हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहीं, जिससे युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान और रूस का समन्वय सिर्फ जमीनी युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार अंतरिक्ष में गश्त कर रहे कम से कम 14 रूसी सैटेलाइट ईरान से वास्तविक काल की भू-स्थानिक, रडार और सिग्नल इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया जानकारियां लगातार साझा कर रही हैं, जिसके चलते ईरानी फौज लगातार खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सफल रही है। इससे अमेरिकी सेनाओं को अच्छा-खासा नुकसान उठाना पड़ा है।

रूस ने ऐसा इसलिए किया है, ताकि अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूस के अति महत्वपूर्ण ठिकानों पर यूक्रेन के जरिये कराए गए हमलों का बदला ले सके। साथ ही अमेरिका के हथियार भंडार को इतना कम किया जा सके कि वह यूक्रेन को अधिक सहायता न पहुंचा पाए। इसका असर दिखाई भी देने लगा है। रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-ईरान संघर्ष के एक साथ चलने की वजह से अमेरिकी सेना के पास रक्षा साजोसामान की भारी किल्लत हो गई है। पेंटागन ने चेतावनी दी है कि अगर इस समय कोई और बड़ा वैश्विक युद्ध छिड़ गया, तो अमेरिका के पास हथियारों का स्टाक पूरी तरह खत्म होने का खतरा है। ईरान और उसके समर्थित गुटों के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी सेना को अपनी इन सबसे आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा है, जिसके चलते अमेरिका ने अपने एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लगभग 80 प्रतिशत स्टाक का इस्तेमाल कर लिया है। अमेरिका के आधुनिक पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स का 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत स्टाक खत्म हो चुका है।

अमेरिका के लिए पश्चिम एशिया में वही स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो उसने रूस के लिए यूक्रेन में उत्पन्न की थी। इस संकट के पीछे कम लागत वाले आधुनिक हाइब्रिड युद्ध का गणित है। रूस और ईरान बहुत कम लागत में हर महीने हजारों की तादाद में आत्मघाती ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहे हैं। इसके विपरीत इन्हें विफल करने के लिए अमेरिका के पैट्रियट जैसे रक्षा सिस्टम को बनाने में बहुत जटिल तकनीक और एडवांस गाइडेंस सिस्टम की जरूरत होती है।

अमेरिकी कंपनियां इन मिसाइलों को उतनी तेजी से नहीं बना पा रही हैं, जितनी तेजी से ये युद्ध के मैदान में खर्च हो रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्पति जेलेंस्की के अनुसार पश्चिम एशिया में मिसाइलें भेजने की वजह से यूक्रेन को पहले के मुकाबले सिर्फ एक-तिहाई एयर-डिफेंस मिसाइलें मिल पा रही हैं। इसका प्रभाव अब चीन के मोर्चे पर भी दिखाई देने लगा है, जहां अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को हथियारों की आपूर्ति में पांच साल तक की देरी होने की चेतावनी दी है। जापान को मिलने वाली टोमाहाक मिसाइलों में दो साल की देरी हो चुकी है। ताइवान भेजी जाने वाली 14 अरब डालर की हथियारों की खेप को बीच में ही रोकना पड़ा है, ताकि अमेरिकी सेना अपने खुद के स्टाक को बचा सके।

जहां ईरान पहले से ही होर्मुज जलमार्ग को बंद करके अपनी ताकत दिखा चुका है, वहीं अब उसके समर्थक यमन के हूतियों के जरिये बाब अल-मंडेब पर कब्जा करके उसने दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों पर अपना शिकंजा कस लिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से हूतियों पर हमले की अपील की थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध और यूक्रेन में खुले मोर्चे के चलते हथियारों की किल्लत के कारण यमन में नया मोर्चा खोलने से मना कर दिया।

अमेरिका के पास इतने उन्नत हथियार और प्रतिरक्षा प्रणालियां नहीं बची हैं कि वह एक साथ ईरान से लड़े, यूक्रेन की मदद करे और यमन में भी एक नया मोर्चा संभाल सके।

अष्टभुजा दुर्गा की शक्ति का प्रतिरूप है स्त्री

स्त्री केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं, बल्कि सृजन, करुणा, सहनशीलता और परिवर्तन की प्रतीक भी है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति स्वरूपा मानने की परंपरा रही है। अष्टभुजा दुर्गा इसी असीम शक्ति, सामर्थ्य और सृजनशीलता का प्रतीक हैं। स्त्री की विशिष्टता इस बात में निहित है कि वह स्वयं के साथ-साथ परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपने मूल स्वभाव के अनुरूप कार्य करता है। करोड़ों वर्षों की उत्क्रांति के पश्चात मनुष्य ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। मानव जीवन में स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार प्रकृति में प्रत्येक तत्व का अपना विशेष कार्य है, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष भी अपनी विशिष्टताओं के साथ जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाते हैं।

स्त्री की शक्ति केवल उसकी शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि उसकी संवेदनशीलता, धैर्य, दूरदर्शिता और निर्माण करने की क्षमता में भी निहित है। एक सच्चे निर्माता का हृदय विशाल होता है और उसकी सोच सीमित दायरों में बंधी नहीं होती। यही गुण स्त्री को परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की प्रेरणा देते हैं।

श्री माताजी निर्मला देवी जी ने स्त्री की इसी विशिष्टता को प्रकृति के उदाहरण के माध्यम से समझाया है। वर्ष 1988 में पेरिस में दिए गए अपने प्रवचन 'इंट्यूशन एंड विमेन' में उन्होंने स्त्री की तुलना धरती माता से और पुरुष की तुलना सूर्य से की। उन्होंने बताया कि धरती माता बिना किसी शिकायत के हमें सुंदर फूल, पेड़-पौधे और जीवनदायी पोषण प्रदान करती है। वह अनेक कठिनाइयों को सहन करते हुए भी सृजन और संरक्षण का कार्य निरंतर करती रहती है। सूर्य और पृथ्वी दोनों अपनी-अपनी विशिष्ट भूमिकाओं के कारण प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं।

यह विचार हमें प्रेरित करता है कि स्त्री को अपनी आंतरिक शक्ति और विशिष्टता को पहचानना चाहिए। दूसरों का अंधानुकरण करने के बजाय अपनी सहज प्रकृति, आत्मविश्वास और सृजनशीलता को विकसित करना ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है।

दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश विशेष महत्व रखता है। श्री माताजी निर्मला देवी जी के अनुसार, आत्मसाक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर निहित दिव्य शक्ति को पहचान सकता है।

स्टारलिंक की दस्तक और भारत की रणनीतिक चिंताएँ

एलन मस्क द्वारा भारत में स्टारलिंक की शुरुआत में हो रही देरी पर आलोचना ने उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाओं के नियमन को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। यह बहस केवल किसी निजी कंपनी को भारतीय बाजार में प्रवेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संप्रभुता, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और संचार व्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण जैसे गंभीर प्रश्न जुड़े हैं। भारत जैसे विशाल और भौगोलिक विविधता वाले देश में उपग्रह इंटरनेट डिजिटल विभाजन को कम करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है, लेकिन इसके साथ जुड़े सुरक्षा जोखिमों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

स्टारलिंक जैसी सेवाएँ पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं। इनकी सहायता से दूरस्थ गाँवों, पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपों और सीमावर्ती इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुँचाई जा सकती है, जहाँ पारंपरिक दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करना कठिन और महँगा होता है। हालाँकि, इन सेवाओं की वैश्विक प्रकृति, पोर्टेबल टर्मिनलों और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता के कारण नियामक संस्थाओं के सामने नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं।

सबसे प्रमुख चुनौती आतंकवादी गतिविधियों में संभावित दुरुपयोग की है। दूरदराज के क्षेत्रों में सक्रिय आतंकवादी संगठन या अन्य गैर-राज्यीय तत्व उपग्रह संचार प्रणालियों का उपयोग अपनी गतिविधियों के समन्वय के लिए कर सकते हैं। मणिपुर में वर्ष 2024 के दौरान स्टारलिंक-ब्रांडेड उपकरण मिलने की खबरों ने इस आशंका को चर्चा में ला दिया था। हालाँकि, किसी उपकरण की बरामदगी अपने आप में उसके वास्तविक उपयोग या किसी संगठन से उसके संबंध का निर्णायक प्रमाण नहीं है। इसलिए सुरक्षा आकलन विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं और तकनीकी जाँच पर आधारित होना चाहिए।

दूसरी चुनौती सीमा पार अपराध और तस्करी से संबंधित है। भारत की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ, विस्तृत समुद्री क्षेत्र और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ सुरक्षा एजेंसियों के लिए पहले से ही चुनौतीपूर्ण हैं। यदि उपग्रह इंटरनेट टर्मिनलों का उपयोग अवैध गतिविधियों के समन्वय में किया जाता है, तो अपराधियों की पहचान और उनके संचार की जाँच कठिन हो सकती है। अंडमान क्षेत्र में वर्ष 2024 में मादक पदार्थों की बरामदगी के संदर्भ में स्टारलिंक उपकरणों की चर्चा भी हुई थी। ऐसे मामलों में उपकरणों की वास्तविक भूमिका की पुष्टि आवश्यक है, क्योंकि केवल उनकी मौजूदगी से तस्करी और उपग्रह नेटवर्क के बीच प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध नहीं होता।

तीसरी चुनौती डेटा संप्रभुता और विदेशी नियंत्रण की है। उपग्रह नेटवर्क का संचालन, तकनीकी प्रबंधन और डेटा-संबंधी कुछ प्रक्रियाएँ भारत से बाहर नियंत्रित हो सकती हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के संचार संबंधी आँकड़ों पर किसका नियंत्रण होगा, उनका प्रसंस्करण कहाँ किया जाएगा और भारतीय कानूनों के अंतर्गत आवश्यक सूचनाओं तक पहुँच कैसे सुनिश्चित होगी। यदि इन विषयों पर स्पष्ट नियम नहीं होंगे, तो जाँच एजेंसियों और नियामकों के लिए अपने कानूनी अधिकारों का प्रभावी प्रयोग कठिन हो सकता है।

चौथी चुनौती वैध निगरानी और कानून प्रवर्तन की है। पारंपरिक दूरसंचार नेटवर्क में सेवा प्रदाताओं, लाइसेंसिंग शर्तों और घरेलू नेटवर्क अवसंरचना के माध्यम से कानूनी निगरानी की व्यवस्था लागू की जा सकती है। उपग्रह इंटरनेट में विदेशी नेटवर्क संचालन और सीमा-पार डेटा प्रवाह के कारण इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए अतिरिक्त तकनीकी क्षमता तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। यदि सेवा प्रदाता भारतीय कानूनों के अनुरूप वैध आदेशों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं, तो आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर अपराध की जाँच प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, निगरानी की शक्तियों का प्रयोग स्पष्ट कानून, आवश्यकतानुपात और जवाबदेही के अधीन होना चाहिए, ताकि नागरिकों की निजता और मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें।

पाँचवीं चुनौती रणनीतिक निर्भरता की है। यूक्रेन युद्ध के दौरान स्टारलिंक की भूमिका ने प्रदर्शित किया कि निजी उपग्रह संचार प्रणालियाँ संकट और युद्ध के समय अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं। ऐसी प्रणालियाँ संचार व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करती हैं, लेकिन किसी विदेशी कंपनी के व्यावसायिक निर्णय, सेवा की शर्तों में बदलाव या तकनीकी व्यवधान पर अत्यधिक निर्भरता राष्ट्रीय हितों के लिए जोखिम बन सकती है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपातकालीन परिस्थितियों में उसकी महत्त्वपूर्ण संचार सेवाएँ किसी एक विदेशी प्रदाता पर निर्भर न रहें।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहले स्पष्ट और प्रभावी लाइसेंसिंग व्यवस्था आवश्यक है। उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार विभाग, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र तथा संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की लागू आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। लाइसेंस, स्पेक्ट्रम आवंटन और सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रियाएँ पारदर्शी, समयबद्ध तथा समान मानकों पर आधारित हों। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अनिश्चितकालीन देरी से बचते हुए संवेदनशील मामलों की समुचित जाँच की जानी चाहिए।

दूसरे, घरेलू नेटवर्क अवसंरचना और डेटा प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए। जहाँ तकनीकी रूप से आवश्यक और व्यवहार्य हो, वहाँ घरेलू गेटवे तथा भारतीय कानूनों के अंतर्गत वैध निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी सेवाओं पर एक जैसा तकनीकी मॉडल थोपने के बजाय जोखिम-आधारित नियमन अपनाना अधिक व्यावहारिक होगा।

तीसरे, उपयोगकर्ता सत्यापन और टर्मिनल पंजीकरण की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकृत उपकरणों के स्वामित्व, पंजीकरण और उपयोग की शर्तों का रिकॉर्ड रखा जाए। चोरी हुए उपकरणों, अनधिकृत टर्मिनलों और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए सेवा प्रदाताओं तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार भौगोलिक प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं, लेकिन उनका आधार स्पष्ट सुरक्षा आकलन होना चाहिए।

चौथे, नियमित साइबर सुरक्षा परीक्षण, स्वतंत्र सुरक्षा लेखा-परीक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ अनिवार्य की जानी चाहिए। सेवा प्रदाताओं को साइबर हमलों, डेटा उल्लंघनों और नेटवर्क व्यवधानों की समय पर सूचना देने तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। साथ ही, भारत को स्वदेशी उपग्रह संचार क्षमताओं, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार में निवेश बढ़ाना चाहिए, ताकि रणनीतिक निर्भरता कम हो सके।

अंततः, उपग्रह इंटरनेट का प्रश्न केवल तकनीक या व्यापार का प्रश्न नहीं, बल्कि डिजिटल अधिकारों, राष्ट्रीय संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती है। भारत को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो दूरस्थ क्षेत्रों तक किफायती इंटरनेट पहुँचाए, निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करे तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं का प्रभावी समाधान भी प्रस्तुत करे। पारदर्शी नियमन, तकनीकी आत्मनिर्भरता, जवाबदेह निगरानी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही भारत डिजिटल प्रगति को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप आगे बढ़ा सकता है।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

राष्ट्रीय हितों के आड़े न आए राजनीति

पिछले दिनों जब केरलम के विझिंजम बंदरगाह से निर्यात-आयात शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह बंदरगाह दुनिया की ओर खुलने वाला द्वार है। खास बात यह है कि इस बंदरगाह का निर्माण अदाणी समूह ने किया है। यह भारत का गहरे समुद्र में बना ऐसा बंदरगाह है, जिसकी देश को वर्षों से रणनीतिक आवश्यकता थी। 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करुणाकरन ने विझिंजम में एक डीप-सी बंदरगाह की परिकल्पना की थी। हालांकि कुछ रिकार्ड कहते हैं कि 1940 में त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर ने यह विचार सुझाया था और इसके आधार पर सर्वेक्षण भी हुआ था। परिकल्पना 1940 की मानें या 1991 की, इतना तो स्पष्ट है कि लंबे समय तक यह परियोजना कागजों में ही रही। जब इसके आकार लेने की बात आई तो प्रश्न उठा कि विझिंजम का डीप-सी पोर्ट बनाएगा कौन, क्योंकि 1995, 2004, 2008 और 2010 में चार प्रयासों के बाद भी कोई कंपनी इसे बनाने का ठेका नहीं ले सकी।

2014 में इसे नए सिरे से तैयार करने की योजना बनाई गई और 2015 में अदाणी समूह के साथ इसे बनाने का समझौता हुआ। भारत में परियोजनाओं को धरातल पर लाने में अक्सर देरी होती ही है, लेकिन इस परियोजना में हुई देरी से देश को कितना नुकसान हुआ, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। भारत अभी तक अपने कंटेनर ट्रैफिक का 75 प्रतिशत कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के बंदरगाहों के जरिये लाता और भेजता है। अब विझिंजम बंदरगाह से निर्यात-आयात शुरू होने से भारत के जहाजों की विदेशी बंदरगाहों के उपयोग पर निर्भरता कम होगी। गहरे समुद्र में बने विझिंजम बंदरगाह की गहराई स्वाभाविक तौर पर बिना खोदाई किए 20 मीटर की है। इसे आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि जहां विझिंजम बंदरगाह है, वहां समुद्र में लगभग 9-10 मंजिला इमारत पानी के भीतर समा जाएगी। प्राकृतिक रूप से इतनी गहराई पर होने से विझिंजम बंदरगाह में नियमित रखरखाव की लागत भी कम रहेगी। गहराई में होने के कारण विझिंजम बंदरगाह बहुत बड़े जहाजों को भी समायोजित-संचालित करने की क्षमता रखता है।

विश्व की बदलती रणनीतिक परिस्थितियों में आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने की चुनौती भारत जैसे विशाल देश के सामने बहुत बड़ी है। विश्व के सामने विझिंजम बंदरगाह भारत के मजबूत होते अंतरराष्ट्रीय समुद्री बुनियादी ढांचे का बड़ा प्रमाण है। विश्व के सर्वाधिक व्यस्ततम पूर्व-पश्चिम समुद्री मार्ग के निकट होने से विझिंजम बंदरगाह के जरिये भारत वैश्विक व्यापार के केंद्र में आ सकता है। इस बंदरगाह से निर्यात-आयात होने का सीधा लाभ देश के छोटे और मझोले उद्योगों को होगा।

-सुनील कुमार महला

भारतीय युवाओं के मस्तिष्क को संकुचित करता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के भारतीय संदर्भ में जहां जनसंख्या 141 करोड़ हो चुकी है और बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार है ज्यादा प्रयोग से लोगों की नौकरियां जाने का बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह बात दुनिया के बड़े अरबपति कारोबारी टेस्ला और एक्स के कारोबारी एलन मस्क ने स्टार्टअप के एक कार्यक्रम में फ्रांस में महत्वपूर्ण अंदाज में कहीं, भविष्य के लिए यह बात एकदम सटीक एवं सार्थक है। एक अन्य अरबपति कारोबारी इयान बैंक्स ने भी इस पर गंभीर चिंता जताई है। यह बात सभी विकासशील देशों के लिए भी लागू हो सकती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नफ्ज़ पढ़कर आपके मस्तिष्क की बात तुरंत पकड़कर उस पर अमल करने लगेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पल्स रेट द्वारा आपके मन की हर बात जानने में सक्षम हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को वैज्ञानिकों ने मानव की सहायता के लिए और देश की बेहतरी के लिए अविष्कार किया है।

अभी तक तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इजरायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में काफी आगे पर अब खाड़ी के देशों विगत 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति केवल तेल के कुए पर न रह कर अन्य योजनाओं पर भी काम करना शुरू कर दिया है और आश्चर्यजनक रूप से यूएई ,सऊदीअरबिया, कतर, मिस्त्र ,जॉर्डन,

मोरक्को और अन्य देशों में यूरोप की तुलना में अब और ज्यादा खर्च करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को अपने देश में बहुत मजबूत बना लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने फायदे हैं उससे ज्यादा विकासशील देशों के लिए यह नुकसान देह भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पल्स रीडिंग और मानसिक विचारधारा को केवल थंब इंप्रेशन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिवाइस पढ़ कर उस पर अमल कर सकता है।इस टेक्नोलॉजी से अमेरिका तथा यूरोपीय देश अब तक दुश्मन की अनेक सूचनाएं बड़ी आसानी से प्राप्त कर उसका सामरिक उपयोग करने में लगे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग रूस अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मिसाइल दागने में यूक्रेन यूक्रेन के विरुद्ध कर रहा है और अब तक यूक्रेन यूरोपीय तथा नाटो देश की मदद से इसी तकनीक के सहारे रूस के विरुद्ध अब तक टिका हुआ है वैसे तो यूक्रेन और रूस का युद्ध में काफी नुकसान हुआ है पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे हैंद्य

विकासशील देशों में इस टेक्नोलॉजी का विकास अभी काफी एडवांस नहीं है इन परिस्थितियों में उनके लिए उनके सामरिक महत्व की चीजें छुपाना दुश्मन देशों के सामने कठिन हो जाएगा और उनकी खुफिया जानकारी शक्तिशाली देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक सूत्र प्राप्त करने के बाद ही पूरी प्राप्त कर सकते हैं.

खाड़ी के देश जिनमें सऊदी अरबिया, कतर ,मिस्त्र, जॉर्डन, यूएई अपने बजट का 34त्न बढ़ा हुआ हिस्सा एआई तकनीक पर लगातार कर रहे हैं। खाड़ी के देश इस टेक्नोलॉजी का उपयोग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यह उनकी भविष्य की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे वे तेल की कमाई से हटकर अन्य साधनों से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकेंद्य यूं एई पहला देश है जिसने 2017 ने इस तकनीक को अपनाया था इसके बाद खाड़ी के देशों में अब टेक्नोलॉजी को अपनाने में होड़ हो गई हैद्य यह सभी देश एआई टेक्नोलॉजी पर लगभग 3 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैंद्य दूसरी तरफ यदि इसका इस्तेमाल अति विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया तो इसका दुरुपयोग जिन देशों के पास इन टेक्नोलॉजी से एडवांस टेक्नोलॉजी है वह पूरी जानकारी निकालने में सक्षम होंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यूरोपीय देश न सिर्फ सामरिक महत्व की चीजों में कर रहे हैं बल्कि मेडिकल साइंस और अंतरिक्ष विज्ञान में भी पूरी तरह हो रहा है और इससे बहुत फायदे भी मिल रहे हैंद्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव प्रजाति के लिए जितना फायदेमंद है दूसरी तरफ उतना ही नुकसान दे और इससे वैश्विक शांति को खतरा भी हो सकता हैद्य राइट एक्टिविस्ट मानते हैं कि रोबोट की तरह इस तरह की विज्ञान पर आधारित चीजें माननीय प्रजाति को खत्म कर सकती है बल्कि उनकी चिंता डेटा सुरक्षा प्रपो गेंडा सर्विलांस के विरुद्ध होने वाले नुकसान पर भी ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खाड़ी के देशों ने एआई के इस्तेमाल पर दिशा निर्देश तय कर उसे जारी किया है हालांकि इस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है फिर भी इसका दुरुपयोग होने से मानव को खतरा भी हो सकता है यह एक वैश्विक चिंता की बात है।

-संजीव ठाकुर

सुप्रीम कोर्ट के आवश्यक न्यायिक फैसलों के उजाले

लोकतंत्र की मजबूती का वास्तविक प्रमाण केवल चुनावों का नियमित आयोजन, संसद में बहुमत अथवा राजनीतिक दलों की लोकप्रियता नहीं है, बल्कि यह है कि संविधान के सामने सत्ता, विपक्ष और सामान्य नागरिक की स्थिति समान हो। जब सामाजिक न्याय, आरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और चुनावी निष्पक्षता जैसे प्रश्न एक साथ राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आते हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यायपालिका वह संवैधानिक संस्था है, जिससे नागरिक यह अपेक्षा करता है कि वह राजनीतिक आग्रहों, सामाजिक दबावों और सत्ता के प्रभाव से मुक्त रहकर न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगी। आज आरक्षण की पात्रता और धर्मांतरण से जुड़े विवादों से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया तथा न्यायालय की गरिमा तक, अनेक प्रश्न इसी अपेक्षा की कसौटी बनकर सामने हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते समय आवश्यक है कि हम न किसी राजनीतिक पक्ष के प्रचारक बनें, न किसी धार्मिक समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह रखें, बल्कि संविधान की भावना और न्याय के व्यापक उद्देश्य को केंद्र में रखें। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण भारतीय संविधान की उन ऐतिहासिक व्यवस्थाओं में है, जिनका उद्देश्य सदियों से चले आ रहे सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता और भेदभाव के दुष्परिणामों को दूर करना है। यह केवल रोजगार अथवा शिक्षा में कुछ अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं, बल्कि उस सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संवैधानिक हस्तक्षेप है, जिसने बड़ी आबादी को लंबे समय तक समान अवसरों से वंचित रखा। इसलिए आरक्षण और धर्मांतरण के संबंध में होने वाली बहस को भावनाओं, धार्मिक आग्रहों अथवा राजनीतिक आरोपों के बजाय संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर समझना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के व्यक्तियों द्वारा धर्मांतरण करने पर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देना और अपने राज्य में इस प्रकार की सुविधा जारी रखना कि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलता रहे, वास्तव में सनातन संस्कृति के आरक्षित वर्गों के हितों को कमजोर करने वाला और धर्मांतरण को परोक्ष रूप से बढ़ावा देने वाला कदम था। यह विडंबना ही है कि एक तरफ कुछ संगठन यह दावा करते हैं कि उनके यहां जातिगत भेदभाव का अस्तित्व नहीं है, वहीं दूसरी ओर वे एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों को अपने पंथ में आने के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलने की पुरजोर वकालत करते हैं। इस प्रकार के दोहरे लाभ और प्रलोभनों के कारण न केवल धर्मांतरण की प्रवृत्ति को बल मिलता है, बल्कि हिंदू समाज को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि धर्मांतरित लोग आरक्षण के साथ-साथ अल्पसंख्यक दर्जे के लाभों का भी अनुचित दोहन करने लगते हैं। हालांकि विभिन्न राज्य सरकारें छल-कपट से होने वाले धर्मांतरण के विरुद्ध कड़े कानून बना रही हैं, फिर भी यह समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका प्रमुख कारण धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर हो रहा इसका दुरुपयोग है। अब समय आ गया है कि इस गंभीर विषय पर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय मिलकर ठोस और प्रभावी कदम उठाएं ताकि इस दुरुपयोग को रोका जा सके।

इसी व्यापक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय का चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवादों पर हस्तक्षेप भी उल्लेखनीय है। 12 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी सहित विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के नेताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की ओर मार्च किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया भी सराहनीय है। भले ही विपक्ष ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, मतदाताओं के नाम हटाए जाने और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, इन आरोपों की सत्यता का निर्धारण न्यायिक परीक्षण और संबंधित अभिलेखों के आधार पर होना चाहिए, लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक को अपनी राजनीतिक इच्छा व्यक्त करने का संवैधानिक अवसर है। इसलिए मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता किसी एक दल का नहीं, पूरे लोकतंत्र का प्रश्न है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करना एक गलत परम्परा का सूत्रपात है।

15 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्षी नेताओं की याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से जवाब माँगा। इससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग जैसी महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के निर्णय भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं। आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि उसके प्रत्येक निर्णय को प्रश्नों से परे मान लिया जाए। इसी प्रकार, किसी निर्णय से असहमति अपने आप में यह प्रमाणित नहीं करती कि आयोग ने अनुचित कार्य किया है। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य आरोपों और तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट करना, निर्णय प्रक्रिया की वैधानिकता जाँचना तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसी घटनाक्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर के मार्च को लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य संबंधित नेताओं से भी जवाब माँगा। न्यायालय की चिंता यह थी कि राजनीतिक प्रदर्शन के माध्यम से न्यायपालिका पर दबाव बनाने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस प्रसंग का मूल्यांकन करते समय यह समझना आवश्यक है कि शांतिपूर्ण विरोध, राजनीतिक असहमति और न्यायालय की गरिमा-तीनों लोकतंत्र के महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। विपक्ष को सरकार और निर्वाचन आयोग से प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन न्यायिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। दूसरी ओर, न्यायालय की गरिमा की रक्षा के नाम पर वैध आलोचना और शांतिपूर्ण असहमति के अधिकार को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। नोटिस जारी होना किसी को दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि उसका पक्ष जानने की न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

यही वह बिंदु है जहाँ न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन का प्रश्न सामने आता है। यदि न्यायपालिका सामाजिक अन्याय, प्रशासनिक मनमानी अथवा संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर मौन रहे, तो आम नागरिक का न्याय व्यवस्था से विश्वास कमजोर हो सकता है। लेकिन यदि न्यायपालिका प्रत्येक राजनीतिक विवाद में स्वयं को निर्णायक नीति-निर्माता की भूमिका में रखे, तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावित हो सकता है। लोकतंत्र की संस्थाएँ एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक-दूसरे को संवैधानिक मर्यादाओं में रखने वाली व्यवस्थाएँ हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कानून तथा उनका क्रियान्वयन संविधान की सीमाओं के भीतर हों। इन तीनों के बीच स्वस्थ संतुलन ही लोकतांत्रिक स्थिरता की आधारशिला है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा उसके आदेशों की कठोरता से अधिक उसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और तर्कपूर्ण निर्णयों से निर्मित होती है।

आज देश को ऐसी न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता है, जो अन्याय के सामने निर्भीक हो, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र के प्रति सजग भी रहे, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, लेकिन राजनीतिक आग्रहों से अप्रभावित रहे, जो संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखे, लेकिन उनकी जवाबदेही को भी सुनिश्चित करे। धर्मांतरण और आरक्षण के प्रश्न पर स्पष्टता, चुनावी विवादों में पारदर्शिता तथा न्यायालय के प्रति सम्मान-ये अलग-अलग विषय दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन सभी के केंद्र में एक ही मूल प्रश्न है कि संविधान की सर्वोच्चता व्यवहार में कैसे सुनिश्चित हो। न्याय का अर्थ किसी पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार भर नहीं है। न्याय वह विश्वास है, जो नागरिक को यह भरोसा देता है कि उसकी आवाज सुनी जाएगी, उसके अधिकारों का निष्पक्ष परीक्षण होगा और शक्तिशाली व्यक्ति या संस्था भी कानून से ऊपर नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय की वास्तविक शक्ति तभी सिद्ध होगी, जब उसका प्रत्येक निर्णय राजनीतिक शोर से ऊपर उठकर संवैधानिक विवेक, सामाजिक संवेदनशीलता और विधिक निष्पक्षता का उदाहरण बने।

-ललित गर्ग

कुसमानिया में शिविर आयोजित, विधायक श्री शर्मा और कलेक्टर श्री सिंह ने किया समस्याओं का त्वरित निराकरण

कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य- विधायक श्री शर्मा

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा स्थानीय स्तर पर उद्योग एवं स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान' के तहत कन्नौद विकासखंड के ग्राम कुसमानिया में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खातेगांव विधायक श्री आशीष शर्मा, कलेक्टर श्री ऋतु राज सिंह और जिला पंचायत सीईओ श्री नवीत कुमार धुर्वे ने नागरिकों की समस्याओं व शिकायतों को सुना और मौके पर ही उनका त्वरित निराकरण किया।

विधायक श्री आशीष शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के साथ प्रशासन स्वयं आपके के बीच आया है। विधायक श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में आगामी रबी सीजन के दौरान फसलों के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा, ताकि किसानों को सिंचाई में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत आपके ही क्षेत्र में आकर आपको विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। आज जिले के सभी आला अधिकारी इस क्षेत्र में मौजूद हैं, ताकि जनता की समस्याओं और शिकायतों का मौके पर ही त्वरित और प्रभावी निराकरण किया जा सके। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी और हितग्राहीमूलक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

कलेक्टर श्री ऋतु राज सिंह ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। शिविर में प्राप्त अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे आवेदन, जिनका नीतिगत अथवा तकनीकी कारणों से मौके पर तत्काल निराकरण संभव नहीं हो सका, उन्हें %सीएम हेल्पलाइन पोर्टल% पर दर्ज किया जा रहा है। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

शिविर स्थल पर शासन के विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी के लिए स्टॉल भी लगाए गए। इन स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों और नागरिकों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की पात्रता, उनके लाभ तथा आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री संजीव जैन और एएसपी श्रीमती सौम्या जैन सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

अमलतास मेडिकल कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया 'विश्व एनाटॉमी दिवस'

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अमलतास मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में 'विश्व एनाटॉमी दिवस' अत्यंत उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अमलतास मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन श्री मयंकराज सिंह भदौरिया ने अपना संदेश देते हुए कहा कि ÷चिकित्सा शिक्षा में एनाटॉमी (शरीर रचना विज्ञान) की भूमिका नींव का पत्थर की तरह है। जब तक एक विद्यार्थी मानव शरीर की संरचना को गहराई से नहीं समझता, तब तक वह एक सफल चिकित्सक नहीं बन सकता। ऐसे रचनात्मक आयोजन छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ उनके व्यावहारिक और कलात्मक दृष्टिकोण को भी निखारते हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर.के. सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि एक कुशल डॉक्टर बनने के लिए मानव शरीर रचना विज्ञान (एनाटॉमी) का गहन ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इस विशेष दिन को स्मरणीय बनाने के लिए एमबीबीएस के छात्र-छात्राओं ने पोस्टर, वॉल पेंटिंग, रंगोली, फेस पेंटिंग तथा टी-शर्ट पेंटिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी रचनात्मकता का परिचय देते हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में अस्पताल निदेशक डॉ. प्रशांत, एनाटॉमी विभागाध्यक्ष डॉ. एम.एल. करखायले सहित फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एवं माइक्रोबायोलॉजी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं संकाय सदस्य उपस्थित रहे। एनाटॉमी विभाग की टीम के कुशल संचालन और समस्त फैकल्टी व स्टाफ के अथक प्रयासों से यह आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। समारोह के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया गया तथा संस्थान के डीन डॉ. ए.के. पीठवा ने सभी का आभार व्यक्त किया।

विधायक शर्मा और कलेक्टर ने कुसमानिया आदिवासी कन्या आश्रम शाला का निरीक्षण कर छात्राओं से किया संवाद

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। विधायक श्री आशीष शर्मा और कलेक्टर श्री ऋतु राज सिंह ने कुसमानिया स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती आदिवासी कन्या आश्रम शाला का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आश्रम में रह रही छात्राओं से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान छात्राओं ने कविताएं भी सुनाई।

विधायक श्री शर्मा एवं कलेक्टर श्री सिंह ने छात्राओं से चर्चा कर उनके शिक्षण स्तर, दैनिक व्यवस्थाओं और आश्रम में मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। छात्राओं के तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री सिंह ने आश्रम शाला के लिए तत्काल एक कंप्यूटर प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने छात्राओं की मांग पर आश्रम का रंग बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्रम में गर्म पानी के लिए अतिरिक्त गीजर लगाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।

निरीक्षण के दौरान विधायक श्री शर्मा और कलेक्टर श्री सिंह ने आश्रम के रसोई घर (किचन) का भी अवलोकन किया। उन्होंने छात्राओं को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की स्वयं जांच की और मेन्यू के अनुसार पौष्टिक व स्वच्छ भोजन देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्कूल के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण करते हुए संस्था प्रमुख को परिसर में समय-समय पर अनिवार्य रूप से साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल ने देवास के विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में संचालित 'जन विश्वास अभियान' के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. संजय गोयल ने देवास जिले के ग्रामीण अंचल के शासकीय विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम जगठा माध्यमिक विद्यालय, शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय थुरिया तथा हाई स्कूल थुरिया पहुंचकर शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्र उपस्थिति और बुनियादी सुविधाओं का जमीनी स्तर पर जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में दर्ज संख्या के विरुद्ध उपस्थिति की स्थिति चिंताजनक पाई गई। माध्यमिक विद्यालय जगठा में कुल दर्ज 45 विद्यार्थियों में से 27 उपस्थित मिले, शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय थुरिया में दर्ज 142 विद्यार्थियों में से 85 विद्यार्थी उपस्थित पाए गए, वहीं हाई स्कूल थुरिया में कुल 71 विद्यार्थियों में से 58 विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रमुख सचिव डॉ. गोयल ने विद्यालयों में विद्यार्थियों के घटते नामांकन और कम उपस्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी तथा संबंधित संस्था प्रधानों को नामांकन वृद्धि हेतु निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव डॉ. गोयल ने नए शैक्षणिक सत्र में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षकों को जनवरी माह से ही घर-घर जाकर पालकों से सघन संपर्क करने के सख्त निर्देश दिए। अभियान के दौरान उन्होंने स्वयं कई पालकों से सीधा संवाद कर बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने तथा उनकी शिक्षा के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया।

निरीक्षण के दौरान डॉ. गोयल ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद स्थापित कर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य संसाधनों का फीडबैक लिया और उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने संस्था प्रभारियों को विद्यार्थियों के व्यावहारिक ज्ञान के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं का नियमित व समुचित उपयोग सुनिश्चित करने और विद्यालय परिसरों, कक्षाओं व शौचालयों में व्यवस्थित साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कृष्णाजीराव पवार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवास की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन रेडक्रॉस, इको क्लब, युवा पर्यटन क्लब एवं उमंग उच्च शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस के माध्यम से आयोजित किया गया। यह शिविर प्रभारी प्राचार्य डॉ. बी. एस. जाधव के निर्देशन में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित हुआ। शिविर में महाविद्यालय के विद्यार्थियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉ. कुश घनघोरिया (मेडिकल ऑफिसर), डॉ. मोनिका कन्नौज (दंत विशेषज्ञ), डॉ. सबीना मंसूरी (मेडिकल ऑफिसर), डॉ. आशा सुमन (नेत्र चिकित्सा सहायक) एवं पवन यादव (नर्सिंग ऑफिसर) ने अपनी सेवाएं दीं। इस स्वास्थ्य शिविर में कुल 76 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें 34 बालक एवं 42 बालिकाएं शामिल थीं। इस अवसर पर महाविद्यालय से डॉ. लीना दुबे, डॉ. मनोज मालवीय, डॉ. रजत राठौर, डॉ. माया ठाकुर, डॉ. निकिता कर्मा, डॉ. रुचि धाकड़ सहित अन्य स्टाफ सदस्य, एन.सी.सी., राष्ट्रीय सेवा योजना, इको क्लब, रेडक्रॉस एवं युवा पर्यटन क्लब के स्वयंसेवक तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। शिविर के सफल आयोजन में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रो. राकेश कोटिया एवं इको क्लब, रेडक्रॉस, युवा पर्यटन क्लब के जितेन्द्र सिंह राजपूत का विशेष सहयोग रहा।

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत ग्राम पिपलानी में शिविर आयोजित

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत भैरूंदा विकासखंड के ग्राम पिपलानी में शिविर एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में कलेक्टर श्री बालागुरू के., पुलिस अधीक्षक श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना तथा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती सर्जना यादव सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनका निराकरण किया तथा पात्र हितग्राहियों को लाभान्ति करने की कार्यवाही की गई।

शिविर में ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य प्रशासन को गांवों तक पहुंचाकर नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना और शासकीय सेवाओं को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाना है।

शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूकता जरूरी-कलेक्टर- मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत भैरूंदा विकासखंड के ग्राम पिपलानी में आयोजित शिविर में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें और ग्रामीण क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को समझें। उन्होंने ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया।

सचिव श्री श्रीमन् शुक्ल ने किया सीहोर जिले का भ्रमण

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के सचिव श्री श्रीमन् शुक्ल ने सीहोर जिले का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका सीहोर में जन्म-मृत्यु पंजीयन से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया तथा पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने तीन हितग्राहियों को जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किए और पंजीयन प्रक्रिया में नागरिकों को आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

श्री श्रीमन् शुक्ल ने कार्यालय कलेक्टर स्थित जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय के माध्यम से संचालित सांख्यिकी संबंधी कार्यों तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति से संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा की। जिला स्तर पर जन्म-मृत्यु पंजीयन की ऑनलाइन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

पत्रकार प्रदीप ठाकुर की माताश्री सुमित्रा ठाकुर का निधन

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पत्रकार प्रदीप ठाकुर की माताश्री एवं ठाकुर गोवर्धन सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती सुमित्रा ठाकुर के आकस्मिक निधन से समाज में शोक की लहर है। उनके निधन पर समाजजनों एवं परिचितों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अंतिम यात्रा निज निवास चामुंडापुरी, राधागंज से शाम 5:30 बजे निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन एवं परिजन शामिल हुए।

कुसमानिया में 'उद्योग संवाद': लखपति दीदियों ने साझा की आत्मनिर्भरता की कहानियां, बोलीं- चौके-चूल्हे से कारोबार तक का सफर किया तय

विधायक आशीष शर्मा और कलेक्टर ने 25 हितग्राहियों को 1 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक ऋण के लिए वितरित किए स्वीकृति पत्र

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत ग्राम कुसमानिया में विधायक श्री आशीष शर्मा, कलेक्टर श्री ऋतु राज सिंह एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नवीत कुमार धुर्वे की उपस्थिति में उद्योगपतियों, स्थानीय उद्यमियों एवं स्व-सहायता समूहों की 'लखपति दीदियों' के साथ उद्योग संवाद का आयोजन किया गया। संवाद में क्षेत्र के औद्योगिक विकास, निवेश को प्रोत्साहन, स्वरोजगार के अवसरों के विस्तार तथा स्थानीय स्तर पर उद्योगों के संचालन में आ रही समस्याओं के निराकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विधायक श्री शर्मा एवं कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 25 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 1 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए।

स्व-सहायता समूहों से महिलाओं को मिल रही नई पहचान- उद्योग संवाद के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने स्व-सहायता समूहों से जुड़ने के बाद जीवन में आए आर्थिक एवं सामाजिक बदलावों की कहानियां साझा कीं। महिलाओं ने बताया कि समूहों से जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही एक महिला ने बताया कि वह प्रतिमाह 20 से 25 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं। बैंकिंग संबंधी कार्यों एवं ऋण प्रक्रिया में सहयोग करने के साथ ही अब वे आत्मविश्वास के साथ लोगों से संवाद कर रही हैं। उन्होंने बताया कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

इसी प्रकार श्रीमती समा चौहान ने बताया कि पहले वे गृहिणी थीं, लेकिन अब जैविक दवाइयां बनाने के साथ किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं। वे अब तक लगभग 125 किसानों को जैविक खेती के संबंध में मार्गदर्शन दे रही हैं तथा इस कार्य से प्रतिमाह 20 से 25 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि समूह के माध्यम से वे अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय हैं। श्रीमती राठौड़ ने भी स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद बढ़े आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि समूह से जुड़कर महिलाओं को घर से बाहर निकलने, अपने हुनर को व्यवसाय में बदलने और स्वयं की पहचान स्थापित करने का अवसर मिला है। क्षेत्र में महिलाएं पापड़ निर्माण, स्कूल ड्रेस तैयार करने, दीपावली पर दीपकों की दुकान लगाने तथा उपार्जन कार्य जैसी गतिविधियों से भी जुड़ रही हैं।

जैविक खेती से लेकर खाद्य प्रसंस्करण तक बढ़ रहे कदम- उद्योग संवाद के दौरान क्षेत्र की उद्यमी श्री शीतल जलोदिया ने उद्यानिकी विभाग के सहयोग से फलोद्यान विकसित करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य पोषित योजना के अंतर्गत उन्होंने लगभग 530 पौधे लगाए हैं तथा जैविक पद्धति से खेती कर रही हैं। पौधे बड़वानी से लाए गए थे और इस कार्य के लिए उन्होंने 80 हजार रुपये का ऋण लिया है। वे स्थानीय बाजार में अपने उत्पादों का विक्रय करना चाहती हैं, लेकिन जैविक उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार उपलब्ध नहीं होने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने टेक्सटाइल वर्क प्लांट स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।

उद्यमी श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अंतर्गत मल्टीग्रेन उत्पाद तैयार करने के लिए उनका ऋण स्वीकृत हुआ है। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। संवाद में महिलाओं द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती और अन्य लघु उद्योगों के विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

महिलाओं को बेहतर बिजनेस प्लानिंग और वित्तीय प्रबंधन के लिए किया प्रेरित- कलेक्टर श्री ऋतु राज सिंह ने महिला उद्यमियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्व-सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं अब किराना दुकान से लेकर रियल एस्टेट और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों तक में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। महिलाएं अपनी मेहनत, कौशल और आत्मविश्वास के बल पर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन, आय-व्यय का सही आकलन, लाभ की गणना तथा बेहतर बिजनेस प्लानिंग के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि नए स्टार्टअप शुरू करने और मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बैंक ऋण एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार और नई इंडस्ट्रीज की स्थापना से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्व-सहायता समूहों की महिलाएं इन अवसरों का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को और अधिक मजबूत बना सकती हैं।

दीपावली पर श्रमिकों को नकद राशि के बजाय उपहार देने की मांग

सेनेटरी एवं सिरामिक श्रमिक संघ ने श्रम कार्यालय में सौंपा आवेदन, श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल को भी लिखेंगे पत्र

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सेनेटरी एवं सिरामिक श्रमिक संघ (भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध) ने रोका बाथरूम प्राइवेट लिमिटेड, देवास के श्रमिकों की मांग पर दीपावली के अवसर पर नकद राशि के बजाय उपहार दिए जाने की मांग की है। इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष धनंजय गायकवाड़ ने श्रम कार्यालय में प्रतिनिधित्व कर रहे अमित दोडवे को आवेदन सौंपकर श्रमिकों की मांग से अवगत कराया। धनंजय गायकवाड़ ने बताया कि रोका बाथरूम प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर श्रमिकों को उपहार के रूप में 1,450 रुपये की नकद राशि दी जाती है। इस वर्ष श्रमिकों की मांग है कि नकद राशि के स्थान पर समान राशि का उपहार प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में उपहार को सम्मान और आत्मीयता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में दीपावली जैसे पर्व पर श्रमिकों को नकद राशि के बजाय उपहार दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। धनंजय गायकवाड़ ने बताया कि इस विषय को लेकर शीघ्र ही प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल को पत्र लिखकर मांग की जाएगी कि मध्यप्रदेश में स्थित कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों को दीपावली के अवसर पर उपहार दिए जाने का नियम लागू किया जाए। इससे श्रमिकों को त्योहार के अवसर पर सम्मानजनक तरीके से उपहार मिल सकेगा। इस अवसर पर सेनेटरी एवं सिरामिक श्रमिक संघ के अध्यक्ष केसर सिंह, महामंत्री जसवंत सहित अन्य पदाधिकारी एवं कंपनी के कर्मचारी उपस्थित रहे।

परिवहन सचिव ने किया सीहोर जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण, नागरिकों को त्वरित और बेहतर सेवाएं देने के निर्देश

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सचिव मध्यप्रदेश सड़क परिवहन एवं आयुक्त जनसंपर्क श्री मनीष सिंह ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत सीहोर जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यालयीन व्यवस्थाओं, अभिलेख संधारण तथा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सेवाओं की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने कार्यालय के विभिन्न कक्षों और पूरे परिसर का निरीक्षण करते हुए परिवहन सेवाओं के संचालन की स्थिति देखी तथा संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान श्री सिंह ने कार्यालय में संधारित किए जा रहे अभिलेखों का अवलोकन किया और दस्तावेजों के व्यवस्थित संधारण के निर्देष दिये। उन्होंने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि कार्यालय में आने वाले नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाएं सरल, सुगम और समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

पप्पी बना के नेतृत्व में बदनावर में मचेगी दशहरे की धूम

81 फीट ऊंचे रावण दहन और विश्व शांति के संदेश के साथ ऐतिहासिक होगा आयोजन

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर में इस बार का दशहरा पर्व बेहद भव्य, अनूठा और ऐतिहासिक होने जा रहा है। चंद्रभानु सिंह मित्र मंडल रावण दहन समिति के तत्वावधान में आगामी 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाले विशाल रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। इस आयोजन को सफलता के शिखर तक पहुँचाने में कार्यक्रम प्रभारी पोपसिंह राठौर (पप्पी बना) अपनी ऊर्जावान और कुशल कार्यशैली से अगुवाई कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में समिति का एक-एक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से जुटा हुआ है। कार्यक्रम प्रभारी पोपसिंह राठौर (पप्पी बना) के सक्रिय मार्गदर्शन और देखरेख में रावण दहन के इस 27वें वर्ष को अब तक का सबसे यादगार आयोजन बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। राठौर के नेतृत्व में सुरक्षा, अनुशासन, मातृशक्ति के सम्मान और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उनकी निरंतर सक्रियता और सुव्यवस्थित प्रबंधन के चलते कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

इस आयोजन का मुख्य आकर्षण धार जिले का सबसे ऊंचा 81 फीट का रावण होगा। इस बार रावण निर्माण की थीम बेहद खास है, जो रूस-यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष की पृष्ठभूमि पर आधारित है। रावण के माध्यम से दुनिया को शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे का कड़ा संदेश देने का अनूठा प्रयास किया जा रहा है, ताकि समाज में प्रेम और एकता की भावना मजबूत हो सके। रावण के दहन के साथ-साथ आकाश में हनुमानजी का दिव्य स्वरूप और आसमान को रोशन करने वाली भव्य आतिशबाजी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इन अलौकिक दृश्यों को देखने के लिए बदनावर नगर सहित आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीण अंचलों में भी जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए माँ एकवीरा मंदिर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो घर-घर जाकर लोगों को आमंत्रण दे रहा है। इसके अलावा, कार्यक्रम के दौरान बदनावर विधानसभा क्षेत्र में समाजसेवा के क्षेत्र में मिसाल कायम करने वाले कर्मठ व्यक्तित्वों और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

आयोजन की सफलता को लेकर चंद्र कलश गार्डन में आयोजित बैठक में संरक्षक चंद्रभान सिंह सोलंकी, कार्यक्रम प्रभारी पोपसिंह राठौर (पप्पी बना), भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रेमचंद परमार, नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह पंवार (फुंदाबापु), शिवराम सिंह रघुवंशी, प्रवीण पाटीदार, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह चौहान, महेश पाटीदार, स्वतंत्र प्रेस क्लब अध्यक्ष मनीष शर्मा, हनुमंत सिंह पवार, चितरंजन सिंह राठौर, राकेश सिंह चौहान, मदन सिंह देवड़ा, शम्भु सिंह, डॉ. कमलसिंह राठौड़, गोलू यादव, गोवर्धन धबाई, शहीद पेंटर, बद्रीलाल जाट, कपील मुकाती, शिवम मुकाती, मोहित राठौड़ सहित अन्य समाजसेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी मीडिया प्रभारी अनुप जायसवाल ने दी। चंद्रभान सिंह सोलंकी, कार्यक्रम प्रभारी पोपसिंह राठौर (पप्पी बना) तथा समस्त समिति सदस्यों ने नगर के समस्त धर्मप्रेमी नागरिकों, सनातनी बंधुओं, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों से इस ऐतिहासिक महा-आयोजन में सहपरिवार शामिल होकर धर्म लाभ लेने और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने की विनम्र अपील की है।

उत्तर और पश्चिम भारत में विस्तार की तैयारी में धनवेस्टर, 2 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय साक्षर बनाने का लक्ष्य

कोलकाता, ÷ महिलाओं पर केंद्रित और सामाजिक प्रभाव के उद्देश्य से कार्यरत वेल्थ मैनेजमेंट फर्म धनवेस्टर उत्तर और पश्चिम भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रही है। इस विस्तार के माध्यम से कंपनी का लक्ष्य अगले 12ङ्ग18 महीनों में 2 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय साक्षरता से जोड़ना है।

अनुष्का सोहम बाथवाल द्वारा स्थापित धनवेस्टर, वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं के साथ कार्यशालाओं और सामुदायिक शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करती है। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को पैसों से जुड़े विषयों पर खुलकर बातचीत करने और सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। कंपनी के कार्यक्रमों से जीवन के विभिन्न चरणों में मौजूद महिलाएं जुड़ी हैं। इनमें बचत और बजट की बुनियादी समझ हासिल करने वाली स्कूली छात्राओं से लेकर निवेश के विकल्पों को समझने वाली पेशेवर महिलाएं और उद्यमी शामिल हैं।

धनवेस्टर की संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुष्का सोहम बाथवाल ने कहा, ÷वित्तीय साक्षरता किसी महिला के जीवन में उपलब्ध विकल्पों को बदल सकती है। फिर भी, आज कई महिलाओं को लगता है कि पैसों और निवेश से जुड़ी बातचीत किसी और पर छोड़ देना ही उनसे अपेक्षित है। उत्तर और पश्चिम भारत में हमारा विस्तार इस सोच को व्यापक स्तर पर बदलने की दिशा में एक कदम है। अगले 12ङ्ग18 महीनों में हम 2 लाख से अधिक महिलाओं तक ऐसी व्यावहारिक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, जो उन्हें अपने वित्तीय निर्णयों की बागडोर स्वयं संभालने में मदद करे। धनवेस्टर का मानना है कि वित्तीय उत्पादों तक पहुंच के साथ उन्हें समझने और उपयोग करने का आत्मविश्वास भी जरूरी है। नए क्षेत्रों में प्रवेश के साथ कंपनी अपनी वित्तीय शिक्षा संबंधी पहलों को अलग-अलग आय वर्गों, लक्ष्यों और अनुभव वाली महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप ढालने की योजना बना रही है। इन पहलों में रोजमर्रा के पैसों के प्रबंधन से लेकर वित्तीय योजना, निवेश और दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण तक के विषय शामिल होंगे।

बाथवाल ने आगे कहा, ÷हमारे लिए सामाजिक प्रभाव की शुरुआत तब होती है, जब कोई महिला पैसों के बारे में सवाल पूछने, योजना बनाने और उस पर अमल करने का आत्मविश्वास हासिल करती है। 2 लाख महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य हमारी दिशा स्पष्ट करता है, लेकिन प्रगति का।

बनेडिया में उप स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

देपालपुर/ अंकित भोला परमार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर जिले के देपालपुर विकासखंड के ग्राम बनेडिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। नए भवन से क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सुविधा मिलेगी। लोकार्पण समारोह में जनपद पंचायत देपालपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु प्रजापति, उप जिला अधिकारी चरणजीत हुड्डा, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुशीला गुमानसिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. माधव हासानी, जिला क्षय अधिकारी इंदौर डॉ. शैलेन्द्र जैन, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. विभा नागर, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. दिलीप शर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनेडिया डॉ. विजय गेहलोत, खंड कार्यक्रम प्रबंधक दिनेश पाटीदार, प्रमोद आर्य एवं गोविंद मिश्रा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग देपालपुर के अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहे। उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के लोकार्पण से गांव एवं आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की उम्मीद है। यह पहल ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मंदिर परिसर में कन्या पूजन एव कन्या भोजका आयोजन किया

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नवरात्रि के पावन पर्व पर विप्र नारी सनातनी संघ द्वारा गुरुवार को नगर के सांकल बावड़ी स्थित मंदिर परिसर में कन्या पूजन एव कन्या भोजका आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नन्हीं कन्याओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। संगठन की महिला सदस्यों ने कन्याओं के चरण पखारकर पूजन किया, उन्हें चुनरी ओढ़ाई और उनका आशीर्वाद लिया। संगठन की वरिष्ठ संरक्षक जयश्री भट्ट एवं मंजुला मेहता ने कहा कि नवरात्रि मां दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना का पावन पर्व है। छोटी कन्याओं में साक्षात माता का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक भी है। इसी भावना के साथ संगठन की महिलाओं ने माता स्वरूप कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन में जयश्री भट्ट, शिवानी अग्निहोत्री, मंजुला मेहता, सीमा शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, नेहा शर्मा, विद्या सिस्टर, कृष्णा जायसवाल, मोनिका पांचाल, मुस्कान जायसवाल, यशोदा पाटीदार, जयमाला गजभिए सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं।

पुरुष कबड्डी टीम जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु किट वितरण के बाद रवाना

बड़नगर/ महेश सोनगरा/ दैनिक मालावा हेराल्ड। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़नगर में जिला स्तरीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही महाविद्यालयीन टीम को किट वितरण कर प्रतियोगिता हेतु शुभकामनाओं के साथ रवाना किया गया। महाविद्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी डॉ. आर. के. कौरव एवं दल प्रभारी प्रो. मनोहर सिंह निंगवाल द्वारा खिलाड़ियों को किट प्रदान की गई। इस अवसर पर साहित्यकार नितेश जोशी जय ने उपस्थित होकर सभी खिलाड़ियों को अपना आशीर्वचन दिया और प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। महाविद्यालय की पुरुष कबड्डी टीम 17 अक्टूबर को उज्जैन स्थित प्रशांती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता करेगी। यह दल वाणिज्य विभाग के प्रो. मनोहर सिंह निंगवाल के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में बड़नगर का प्रतिनिधित्व करने के लिए रवाना हो रहा है। प्रतियोगिता में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़नगर की टीम की कमान सावन मसार (बी.ए. तृतीय वर्ष) संभालेंगे। टीम के रवाना होने पर महाविद्यालय परिवार, शिक्षकों एवं साथी विद्यार्थियों ने सभी खिलाड़ियों को जीत के लिए हार्दिक बधाई एवं अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

दशहरा महापर्व पर रावण दहन होना चाहिए या नहीं? रावण की विद्वत्ता, मर्यादा और धर्म के वास्तविक संदेश पर विचार

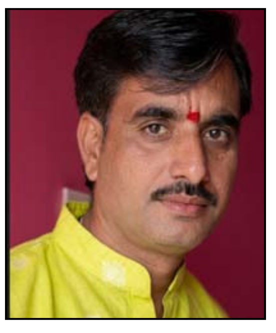

आलोट/ राकेश चौहान/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सनातन धर्म में विजयादशमी अर्थात् दशहरा महापर्व का विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व है। यह पर्व भगवान श्रीराम की रावण पर विजय, धर्म की अधर्म पर विजय तथा सदाचार की दुराचार पर विजय का प्रतीक माना जाता है। देश के अधिकांश भागों में इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। इस परंपरा के माध्यम से समाज को संदेश दिया जाता है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और संपन्न क्यों न हो, यदि वह अहंकार, अन्याय और अधर्म का मार्ग अपनाता है, तो अंततः उसका पतन निश्चित है।

लेकिन वर्तमान समय में रावण दहन की परंपरा को लेकर कुछ विद्वानों और ब्राह्मण संगठनों द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं। उनका तर्क है कि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह वेदों का ज्ञाता, भगवान शिव का अनन्य उपासक, तपस्वी, विद्वान और ब्राह्मण कुल में जन्मा महापंडित था। ऐसे में प्रतिवर्ष उसके पुतले जलाना क्या उचित है? क्या रावण दहन का स्पष्ट उल्लेख मूल धार्मिक ग्रंथों में मिलता है? और क्या किसी विद्वान के दोषों के कारण उसकी संपूर्ण विद्वत्ता को नकार देना उचित है?

ये प्रश्न विचारणीय हैं। इनका उत्तर किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि रामायण के प्रसंगों, धर्म के सिद्धांतों और विवेकपूर्ण चिंतन के आधार पर दिया जाना चाहिए।

रावण की विद्वत्ता को नकारना उचित नहीं- रामायण की परंपरा में रावण को अत्यंत शक्तिशाली, तपस्वी, विद्वान और शिवभक्त राजा के रूप में चित्रित किया गया है। वह महर्षि विश्रवा का पुत्र तथा ऋषि पुलस्त्य के वंश से संबंधित था। उसकी विद्वत्ता, तपस्या, शास्त्रज्ञान और राजनीतिक सामर्थ्य का वर्णन रामकथा के अनेक प्रसंगों में मिलता है।

रावण को वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता है। उसकी विद्वत्ता का उल्लेख करते समय यह समझना चाहिए कि ज्ञान और चरित्र दो अलग-अलग विषय हैं। किसी व्यक्ति का विद्वान होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके सभी आचरण भी धर्मसम्मत होंगे।

रावण की महानता के कुछ पक्षों को स्वीकार करना और उसके अनुचित कर्मों की आलोचना करना परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं। एक निष्पक्ष दृष्टिकोण यही है कि उसके ज्ञान का सम्मान किया जाए, लेकिन उसके अधर्म को उचित नहीं ठहराया जाए।

रावण के विषय में प्रचलित कथन कि वह ऐसा विद्वान था, जिसके समान न भूतकाल में कोई हुआ और न भविष्य में होगा, उसकी असाधारण विद्वत्ता की प्रशंसा व्यक्त करता है। हालांकि इसे किसी प्रमाणित शास्त्रीय उद्धरण के रूप में प्रस्तुत करने से पहले उसके मूल स्रोत की पुष्टि आवश्यक है।

चारों वेदों का ज्ञान होने पर भी रावण का पतन क्यों हुआ?

सनातन धर्म की एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है; उस ज्ञान को जीवन में उतारना भी आवश्यक है। वेद, उपनिषद्, रामायण और महाभारत की शिक्षाओं का मूल उद्देश्य मनुष्य को सत्य, संयम, कर्तव्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है।

रावण की कथा इसी तथ्य को स्पष्ट करती है कि महान ज्ञान और सामर्थ्य के बावजूद यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रखता, तो उसका विवेक कमजोर पड़ सकता है।

रावण का सबसे बड़ा नैतिक अपराध माता सीता का हरण था। सीता जी को उनके पति भगवान श्रीराम से अलग करके लंका ले जाना और उचित परामर्श मिलने के बावजूद उन्हें वापस न करना उसके पतन का प्रमुख कारण बना। उसके भाई विभीषण सहित अनेक शुभचिंतकों ने उसे समझाया, लेकिन उसने अपने अहंकार और हठ को नहीं छोड़ा।

इसलिए रावण की कथा का संदेश यह नहीं है कि विद्वान व्यक्ति का अपमान किया जाए। इसका संदेश यह है कि विद्वत्ता तभी सार्थक होती है, जब उसके साथ सदाचार, आत्मसंयम और धर्मपालन भी हो।

क्या रावण दहन का उल्लेख वेदों और रामायण में मिलता है?

यह प्रश्न वर्तमान विवाद का प्रमुख विषय है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्रीराम और रावण के युद्ध, रावण के वध तथा उसके बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है। रामचरितमानस में भी लंका युद्ध और रावण वध का विस्तृत प्रसंग है।

यहाँ एक महत्त्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। रावण वध और रावण दहन एक ही घटना नहीं हैं। रावण वध रामकथा का प्रसंग है, जबकि दशहरे पर रावण के पुतले का सार्वजनिक दहन एक सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है, जो भगवान श्रीराम की विजय का प्रतीक बन गई है।

यदि किसी ग्रंथ में आज के स्वरूप में विशाल पुतला बनाकर जलाने की विधि स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, तो केवल इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि वर्तमान परंपरा अनिवार्य रूप से गलत है। इसी प्रकार, किसी परंपरा का प्राचीन होना अपने आप में उसके प्रत्येक स्वरूप के शास्त्रीय होने का प्रमाण भी नहीं है।

इस विषय पर विद्वानों को संबंधित ग्रंथों के मूल पाठ, अध्याय, श्लोक और परंपरा के ऐतिहासिक विकास के आधार पर चर्चा करनी चाहिए। किसी कथन को शास्त्रीय प्रमाण बताने से पहले उसका मूल संदर्भ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

रावण दहन का विरोध करने वाले विद्वानों की बात कहाँ तक उचित है?

किसी भी धार्मिक परंपरा पर प्रश्न उठाना अपने आप में अनुचित नहीं है। यदि कोई विद्वान यह पूछता है कि रावण दहन की परंपरा का शास्त्रीय आधार क्या है, तो उसके प्रश्न का उत्तर तर्क, प्रमाण और शास्त्रार्थ से दिया जाना चाहिए।

रावण की विद्वत्ता, ब्राह्मण कुल में जन्म और शिवभक्ति का सम्मान करने की बात भी विचारणीय है। समाज को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी पात्र के प्रति असहमति या आलोचना का अर्थ उसके जन्म, जाति या पूरे समुदाय का अपमान करना नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, रावण दहन की परंपरा का समर्थन करने वालों का तर्क है कि यह रावण के ब्राह्मणत्व या उसके ज्ञान के विरुद्ध अभियान नहीं, बल्कि उसके अधर्म और अहंकार के अंत का प्रतीक है। इस दृष्टिकोण में पुतला किसी जाति या समस्त ब्राह्मण समाज का प्रतीक नहीं, बल्कि बुराइयों का प्रतीक माना जाता है। अतः दोनों पक्षों को एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए संवाद करना चाहिए। किसी भी पक्ष को बिना पर्याप्त प्रमाण के धर्मविरोधी कहना अथवा किसी की आस्था का उपहास करना उचित नहीं है।

क्या रावण दहन बंद कर देना चाहिए?

इस प्रश्न का उत्तर सभी क्षेत्रों और समुदायों की धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। भारत में रामायण की अनेक क्षेत्रीय और लोक परंपराएँ प्रचलित हैं। कुछ स्थानों पर रावण दहन किया जाता है, जबकि कुछ समुदाय रावण को विद्वान, पूर्वज या पूजनीय पात्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि रामकथा के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोणों में विविधता रही है।

पंडित ईश्वर शर्मा श्री महामाया महिषासुर मर्दिनी पुजारी विक्रमगढ़ आलोट

जनविश्वास अभियान के तहत् कलेक्टर एवं एसपी ने मोड़ी में सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र, राशन दुकान और उर्वरक वितरण केन्द्र का किया निरीक्षण

आगर-मालवा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना एवं पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने शुक्रवार को जन विश्वास अभियान के तहत् ग्राम मोड़ी में शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कर ग्रामीणों और उपभोक्ताओं को राशन वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पीओएस मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया, उपलब्ध स्टॉक एवं अब तक वितरित की गई राशन सामग्री की मात्रा एवं उपभोक्ताओं की संख्या आदि की जानकारी ली।

कलेक्टर ने ग्राम मोड़ी में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के उर्वरक वितरण केन्द्र का निरीक्षण कर ई-टोकन के माध्यम से उर्वरक वितरण कार्य का अवलोकन भी किया। उन्होंने समिति प्रबंधक से उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति तथा अग्रिम उठाव के बारे में जानकारी ली।

कलेक्टर ने इस भ्रमण के दौरान शासकीय उमावि परिसर में स्थित सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 4 मोड़ी का निरीक्षण कर केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति, टीकाकरण, गरम पका भोजन वितरण, नाश्ता वितरण, बच्चों के वजन लेने एवं टीकाकरण पंजी का संधारण, शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों की जानकारी ली। कलेक्टर ने नियमित रूप से आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन की सराहना की। आंगनवाड़ी के बच्चों ने पुष्प गुच्छ भेंटकर कलेक्टर एवं एसपी का स्वागत् किया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव गुप्ता, एसडीएम देवकुंवर सोलंकी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर द्वारा पशु आहार निर्माण यूनिट एवं गौ-पालन कैन्द्र का निरीक्षण - कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना एवं एसपी दिलीप सोनी ने ग्राम मोड़ी के समीप अनिल पाटीदार द्वारा स्थापित पशु आहार निर्माण यूनिट एवं गौ-पालन केन्द्र का निरीक्षण कर विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने पाटीदार द्वारा ग्रामीणों से ढ़ाई रूपए किलों के भाव से हरी मक्का के पौधें खरीदकर उन्हें अपनी यूनिट में लाकर पुश आहार साइनेज तैयार करने के कार्य की सराहना की। कलेक्टर ने इसके साथ ही पाटीदार द्वारा स्थापित गौ-पालन केन्द्र में गिर नस्ल की 58 गायों के पालन के कार्य का अवलोकन भी किया और गौपालन से हो रहे लाभ के बारे में चर्चा की। कलेक्टर ने ग्राम पायली में जुगलकिशोर पाटीदार द्वारा अपने खेत में साढ़े तीन हजार संतरे के पौधें लगाकर तैयार किये गए संतरा बागवान का निरीक्षण किया और संतरे के पौधें की खरीदी, लागत, बगीचा तैयार करने में आई लागत, फल बहार एवं विपणन की व्यवस्था आदि की जानकारी भी ली।

इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ बीएस सोलंकी, एसडीएम देवकुंवर सोलंकी, एसडीओपी देवनारायण यादव, उप संचालक कृषि गोपेश पाठक, उप संचालक उद्यानिकी अर्जुन राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

देपालपुर में आज सजेगी भव्य भजन संध्या, पद्मश्री अनुराधा पौडवाल सहित प्रसिद्ध भजन गायक देंगे प्रस्तुति

देपालपुर/ अंकित भोला परमार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर के अति प्राचीन देवी माता मंदिर में शनिवार, 17 अक्टूबर को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष चिन्टू वर्मा के नेतृत्व में आयोजित होने वाली यह भजन संध्या लगातार 31 वर्षों से श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजित की जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की प्रेरणा से वर्ष 1996 में शुरू हुई यह भक्ति परंपरा आज भी निरंतर जारी है। इस वर्ष भजन संध्या में विश्व प्रसिद्ध भजन गायिका पद्मश्री अनुराधा पौडवाल अपनी सुमधुर प्रस्तुतियां देंगी। उनके साथ सुप्रसिद्ध गायिका कविता पौडवाल और प्रसिद्ध भजन गायक गजेन्द्र प्रताप सिंह भी भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्तिरस से सराबोर करेंगे। आयोजन को लेकर धर्मप्रेमियों में उत्साह है। आज शनिवार शाम 7 बजे से शुरू होने वाली इस भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेगे। आयोजक चिन्टू वर्मा ने समस्त धर्मप्रेमी नागरिकों से आयोजन में शामिल होकर भक्ति रस का लाभ लेने की अपील की है।

शिवसेना ने निकाली पंढरीनाथ कुंड से मां कालिका के दरबार तक विशाल चुनर यात्रा

चुनर यात्रा का नगर में जगह-जगह पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत

बड़नगर/ महेश सोनगरा/ दैनिक मालावा हेराल्ड। शिवसेना के युवा सेना प्रदेश अध्यक्ष प्रभात पुरानिया व नगर अध्यक्ष संतोष बेगैरवाल के नेतृत्व में एक विशाल चुनर यात्रा का आयोजन किया गया चुनर यात्रा का शुभारंभ स्थानीय पंढरीनाथ कुंड से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गो से होती हुई मां कालिका के दरबार में किला प्रांगण पर पहुंची जहां पर माता को चुनरी चढ़ाई गई शिवसेना द्वारा निकाली गई इस भव्य चुनर यात्रा का नगर वासियों ने भव्य स्वागत करते हुए जगह-जगह मंचों के माध्यम से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और चुनर यात्रा के आयोजक शिवसेना युवा सेना प्रदेश अध्यक्ष प्रभात पुरानीया व नगर अध्यक्ष संतोष बेगैरवाल का भी पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया इस चुनर यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया चुनर यात्रा के आगे टैंकर के माध्यम से पानी का छिड़काव किया गया तो उसके पीछे डमरु के साथ मंडली ने भी डमरू वादन किया इसके बाद डीजे के द्वारा माता के भजनों के साथ चुने यात्रा में शामिल महिलाएं माता के भजनों पर नाचते गाते पूरे रास्ते चलते रहे और अंत में चुनर यात्रा किला प्रांगण स्थित मां कालिका के दरबार पहुंची जहां पर माता को चुनार अर्पित की गई एवं साबूदाना खिचड़ी का वितरण किया गया। चुनर यात्रा के दौरान पूरा नगर माता की भक्ति में डूबा नजर आया कहीं पुष्प वर्षा तो कहीं चुनर यात्रा में शामिल भक्तों को फल वितरण भी किए गए।

आगर में डॉक्टरों में आक्रोश, कथित नेता पर अवैध वसूली का आरोप

आगर मालवा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला चिकित्सालय आगर में 16 अक्टूबर को Government Doctors Association (GDA) जिला इकाई आगर की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में डॉ. के.के. सारंगिया के साथ हुई घटना को लेकर चिकित्सकों ने गहरा रोष व्यक्त किया। एसोसिएशन का आरोप है कि एक कथित नेता द्वारा अवैध वसूली की मांग की गई, डॉ. सारंगिया को धमकाया गया और दबाव बनाने के लिए फेक न्यूज प्रसारित की गई।

डॉक्टरों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्य और पेन ड्राइव के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

तीन बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं दिनांक 02.10.2026 को सुनीता सारंगिया द्वारा एस पी व थाना प्रभारी आगर को आवेदन दिया वहीं 13.10.2026 को डॉ. के.के. सारंगिया द्वारा एस पी , थाना प्रभारी को आवेदन वही दिनांक 14.10.2026 को सुनीता सारंगिया द्वारा पुनः आवेदन दिया इसके बाद भी

पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से जिले के चिकित्सकों में आक्रोश है।

जीडीए के 4 चरण - पहला दिनांक 16.10.2026 से काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध।

दूसरा कार्रवाई न होने पर दिनांक 21.10.2026 से आंदोलन तेज

तीसरा उसके बाद भी कार्रवाई न होने पर जिले में पेन डाउन - एमएलसी, पोस्टमार्टम व अन्य निर्धारित कार्य बंद। चौथा अंतिम चरण में प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे एसोसिएशन ने कहा है कि सूचना के बाद यदि कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो उसकी जिम्मेदारी चिकित्सा अधिकारियों की नहीं होगी।

संभागायुक्त का विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण

मेडिकल डिवाइस पार्क और बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल का किया निरीक्षण; आईटी पार्क फेज-3 का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर स्वीकृति लेने के निर्देश

उज्जैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। उज्जैन संभाग में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए संभागायुक्त आशीष सिंह ने विक्रम उद्योगपुरी, मेडिकल डिवाइस पार्क और मेसर्स बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक इकाइयों की गतिविधियों, निवेश की स्थिति और रोजगार के अवसरों की जानकारी ली। विक्रम उद्योगपुरी और मेडिकल डिवाइस पार्क में अब तक 161 औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से 24,021 करोड़ रुपये का निवेश आया है। इन परियोजनाओं से कुल 50,369 लोगों के लिए रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं। संभागायुक्त ने आईटी पार्क फेज-3 का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने और स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश गुप्ता, डीआईजी श्री नवनीत भसीन और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी), क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के कार्यकारी संचालक श्री राजेश राठौड़ उपस्थित रहे। अधिकारियों ने औद्योगिक गतिविधियों, संचालित इकाइयों और निर्माणाधीन परियोजनाओं की जानकारी संभागायुक्त को दी।

विक्रम उद्योगपुरी में निवेश से बढ़े रोजगार के अवसर- विक्रम उद्योगपुरी के फेज-1 में 67 औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से 6,422 करोड़ रुपये का निवेश आया है। इन इकाइयों से 19,763 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। वहीं, फेज-2 में 20 कंपनियों ने 14,335 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे 15,730 लोगों के लिए रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, मेडिकल डिवाइस पार्क में 74 उद्योगों के माध्यम से 3,264 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इनसे 14,876 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। इस प्रकार तीनों श्रेणियों के आंकड़ों के अनुसार, कुल 161 औद्योगिक इकाइयों में 24,021 करोड़ रुपये का निवेश और 50,369 रोजगार के अवसर दर्ज किए गए हैं।

मेडिकल डिवाइस पार्क का निरीक्षण- संभागायुक्त आशीष सिंह ने मेडिकल डिवाइस पार्क का निरीक्षण कर वहां मेडिकल उपकरणों के निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों की जानकारी ली। अधिकारियों ने पार्क में विकसित की जा रही सुविधाओं और निवेश की संभावनाओं से अवगत कराया। मेडिकल उपकरण निर्माण से जुड़ी इकाइयों के विस्तार से क्षेत्र में आधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद है।

बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल की गतिविधियां देखीं-संभागायुक्त आशीष सिंह ने पुलिस महानिरीक्षक राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन और एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौड़ के साथ उज्जैन स्थित मेसर्स बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल का भी अवलोकन किया। अधिकारियों ने औद्योगिक इकाई की गतिविधियों और संचालन का जायजा लिया। निरीक्षण का उद्देश्य क्षेत्र में संचालित उद्योगों की स्थिति और औद्योगिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना था।

आईटी पार्क फेज-3 का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश- निरीक्षण के बाद संभागायुक्त एमपीआईडीसी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति और आगामी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में कार्यकारी संचालक राजेश राठौड़ ने भविष्य की औद्योगिक योजनाओं और आईटी पार्क फेज-3 की तैयारियों की जानकारी दी।

संभागायुक्त ने आईटी पार्क फेज-3 का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने, आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने और स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए। आईटी पार्क के विस्तार से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद है।

सात विदेशी कंपनियों ने किया निवेश- बैठक में एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौड़ ने बताया कि उज्जैन संभाग में सात विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश किया है। इनमें से छह कंपनियों ने उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी में और एक कंपनी ने देवास के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश किया है। इनमें से कुछ कंपनियों ने अपने उद्योगों का संचालन भी शुरू कर दिया है। विदेशी कंपनियों की भागीदारी से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार और रोजगार सृजन को गति मिलने की संभावना है।

मजदूरों से चर्चा कर रोजगार की जानकारी ली, किया वृक्षारोपण- संभागायुक्त आशीष सिंह ने जनकल्याण योजना के अंतर्गत रोजगार विकास और मजदूर कल्याण को लेकर मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने श्रमिकों से चर्चा कर रोजगार की उपलब्धता, रोजगार के अवसरों और रोजगार से जुड़ी स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण भी किया।

औद्योगिक विकास कार्यों की सराहना- बैठक में संभागायुक्त आशीष सिंह ने क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक विकास कार्यों और योजनाओं की सराहना की। उन्होंने निवेश संबंधी प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई करने, औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने और भविष्य की योजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही आईटी पार्क फेज-3 के प्रस्ताव को शीघ्र तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान अंतर्गत रायपुरिया में जिला स्तरीय जन विश्वास शिविर आयोजित

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत शुक्रवार को पेटलावद विकासखंड के रायपुरिया क्लस्टर में जिला स्तरीय जन विश्वास शिविर का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया की उपस्थिति में किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को सुनकर उनके निराकरण की कार्यवाही की गई। इस दौरान विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र एवं डेमो चेक वितरित किए गए।

शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता ङ्क मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया- महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत पेटलावद से ही की गई थी। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में जन विश्वास शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा है कि प्रत्येक शुक्रवार को जिला अधिकारी मैदानी क्षेत्रों में उपस्थित रहकर शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करें, आमजन से संवाद स्थापित करें तथा उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता एवं समयबद्धता के साथ निराकरण सुनिश्चित करें। इसी उद्देश्य से शुक्रवार को बैठकों के स्थान पर मैदानी निरीक्षण एवं जनसमस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है।

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे शिविरों में उपस्थित होकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा पात्रतानुसार उनका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन का समन्वित प्रयास आवश्यक है। शिविर में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्रतानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि पेटलावद क्षेत्र सांस्कृतिक, राजनीतिक, कृषि, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। माही बांध के माध्यम से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होने से यहां कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज क्षेत्र में आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए प्रगतिशील किसानों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उस सपने के सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान अंतर्गत मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने हितग्राहियों को सौंपी स्वामित्व योजना की निःशुल्क रजिस्ट्री

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत रायपुरिया में आयोजित जन विश्वास शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने स्वामित्व योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क रजिस्ट्री प्रदान कर लाभान्वित किया।

शिविर के दौरान मंत्री सुश्री भूरिया द्वारा स्वामित्व योजना अंतर्गत श्रीमती प्रियंका आशीष त्रिवेदी निवासी 122, नीम चौक, रायपुरिया, श्री नानुडा पिता सडीया निवासी ग्राम कनाकुआं एवं श्री हरसिंह पिता कालू निवासी ग्राम कनाकुआं, जिला झाबुआ को निःशुल्क रजिस्ट्री प्रदान की गई।

स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान की जा रही है, जिससे हितग्राहियों को अपनी संपत्ति का वैधानिक दस्तावेज प्राप्त हो रहा है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति संबंधी अधिकार प्रदान कर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।

इस दौरान जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट, पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र पाटीदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, अपर कलेक्टर श्री सी एस सोलंकी, सहायक कलेक्टर सुश्री आयुषी बंसल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद श्रीमती रीतिका पाटीदार एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

विद्युत विभाग तीन दिन में लो-वॉल्टेज की समस्या का समाधान सुनिश्चित करें- डॉ. मीना

सोसायटी के खाद गोदाम के लिये भी शीघ्र ही होगा जमीन का आवंटन

सुसनेर/ गिरिराज बंजारिया/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सेवा संकल्प एवं जन विश्वास अभियान के तहत् सुसनेर विकास खण्ड में ग्राम मोड़ी में कलस्टर स्तरीय शिविर शुक्रवार को आयोजित किया गया। कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना, एसपी दिलीप सोनी, जिला पंचायत सीईओ बीएस सोलंकी, जिला पंचायत सदस्य कालूसिंह सिसौदिया, बजरंग पाटीदार, जनपद उपाध्यक्ष बाबूलाल यादव एवं सोसायटी अध्यक्ष राधेश्याम यादव सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 23 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निराकरण संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही कर के मंच से अवगत कराया।

इस मौके पर कलेक्टर डॉ. मीना ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्रामीणों की प्रमुख मांग एवं समस्या लो-वॉल्टेज की रही है, इस पर उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों से सुबह ही चर्चा की है। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दो-तीन दिन में लो-वॉल्टेज की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की कमी को देखते हुए नवीन चिकित्सक की पद स्थापना का आदेश जारी कर दिया गया है। सोसायटी के गोदाम भवन के लिये जमीन आवंटन की मांग पर कलेक्टर ने कहा कि इसके लिये शीघ्र ही उपयुक्त भूमि का आवंटन कर दिया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक सोनी ने राहवीर योजना, प्रधानमंत्री राहत योजना एवं सायबर अपराध से बचाव एवं सुरक्षा के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि राहवीर योजना के तहत् सड़क दुर्घटना में घायलों की त्वरित मदद कर उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीर से किसी प्रकार की कोई पुछताछ नहीं की जावेगी और उसे प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। पीएम राहत योजना के तहत् घायलों को अस्पतालों में डेढ़ लाख रूपये तक का निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, अब कोई भी सड़क दुर्घटना में घायल मरीज को तत्काल नजदिकी अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका निःशुल्क उपचार करवा सकेगा। सोनी ने कहा कि जागरूकता से ही अपराधों से बचा जा सकता है। उन्होंने सायबर हेल्पलाईन नम्बर 1930 एवं पुलिस सहायता केन्द्र के नम्बर 112 के बारे में बताते हुए कहा कि सायबर अपराध के संबंध में उक्त हेल्पलाईन पर कॉल करने से किसी भी खाते से निकाली गई राशि उसी समय फ्रीज हो जाती है औरपीड़ित को उसकी राशि वापस मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती।

कार्यक्रम को जिपं सदस्य कालूसिंह सिसौदिया, बजरंग पाटीदार, बाबूलाल यादव, राधेश्याम यादव आदि ने भी सम्बोधित किया। एसडीओपी देवकरण यादव ने राहवीर योजना के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर अतिथियों ने कृषि विभाग की ओर से 50 प्रतिशत अनुदान पर धूलचन्द्र गुर्जर एवं भगवान सिंह गुर्जर को मिनी स्प्रींकलर का स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये। विभिन्न विभागों के जिलाधिकारियों ने विभागीय जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देकर उनका लाभ लेने की प्रक्रिया भी विस्तार से बताइ। प्रारंभ में अतिथियों ने मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुश्री अंजना जैन ने स्वागत् गीत एवं छात्रा जया, दीपिका और पायल ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की।

सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम बंसिया, सरपंच गोपाल भिलाला ने सभी अतिथियों को स्वागत् किया। इस मौके पर एसडीएम श्रीमती देवकुंवर सोलंकी, जनपद सीईओ अभिषेक यादव सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

पॉलीहाउस में गुलाब की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकसित करने के दिए निर्देश

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने जिले के विभिन्न ग्रामों में उद्यानिकी विभाग के हितग्राहियों के खेतों, पॉलीहाउस एवं शेडनेट हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कृषकों से उद्यानिकी फसलों के उत्पादन, आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग एवं खेती में आने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ. भरसट ने ग्राम रायपुरिया निवासी कृषक श्री नंदलाल पाटीदार के खेत का निरीक्षण किया। कृषक द्वारा एक हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद के लगभग 2400 पौधे लगाए गए हैं, जिनमें ताइवान अमरूद की विएनार बिही एवं रेड डायमंड जैसी किस्में शामिल हैं। कलेक्टर ने अमरूद की खेती एवं उत्पादन संबंधी जानकारी प्राप्त की।

पॉलीहाउस में गुलाब की खेती का निरीक्षण, क्लस्टर विकसित करने के निर्देश- कलेक्टर ने ग्राम बरवेट निवासी श्रीमती सुनीता रामेश्वर पाटीदार के पॉलीहाउस का निरीक्षण किया, जहां उनके द्वारा पहली बार पॉलीहाउस में गुलाब की खेती की जा रही है। कलेक्टर ने गुलाब की खेती की प्रक्रिया, उत्पादन एवं विपणन संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने गुलाब की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर विकसित करने तथा फूलों की कटाई में आधुनिक मशीनों के उपयोग के निर्देश दिए। इस दौरान कृषक द्वारा फसल पर सब्सिडी प्रदान किए जाने की मांग भी रखी गई। कलेक्टर डॉ. भरसट ने उद्यानिकी फसलों को राजस्व गिरदावरी में शामिल किए जाने के संबंध में पटवारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान अंतर्गत कलेक्टर डॉ. भरसट ने रायपुरिया में विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने रायपुरिया क्षेत्र में विभिन्न शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं संचालित कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षणिक व्यवस्थाओं, पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन तथा निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुरिया में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा- कलेक्टर डॉ. भरसट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुरिया का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकीय स्टाफ, दवाइयों की उपलब्धता एवं संस्थागत प्रसव की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि स्वास्थ्य केंद्र में 2 चिकित्सक एवं 4 नर्सिंग स्टाफ कार्यरत हैं। केंद्र में प्रतिमाह औसतन 60 प्रसव तथा प्रतिदिन लगभग 30 मरीजों की ओपीडी होती है।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र में अधोसंरचना संबंधी समस्याओं का निराकरण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराने के निर्देश दिए। साथ ही पोस्टमार्टम कक्ष का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए पोस्टमार्टम की सुविधा प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित 290 प्रकार की दवाइयों में से अनुपलब्ध दवाइयों की समीक्षा कर आगामी तीन माह की कार्ययोजना तैयार करने तथा दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय अलस्याखेड़ी का निरीक्षण- कलेक्टर डॉ. भरसट ने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय अलस्याखेड़ी का निरीक्षण कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्र-छात्राओं से संवाद कर उनकी शैक्षणिक दक्षता का आकलन किया तथा विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाकर उनकी पठन क्षमता की जानकारी ली।

जनविश्वास अभियान के तहत् कलेक्टर एवं एसपी ने मोड़ी में सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र, राशन दुकान और उर्वरक वितरण केन्द्र का किया निरीक्षण

सुसनेर/ गिरिराज बंजारिया/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना एवं पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने शुक्रवार को जन विश्वास अभियान के तहत् ग्राम मोड़ी में शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कर ग्रामीणों और उपभोक्ताओं को राशन वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पीओएस मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया, उपलब्ध स्टॉक एवं अब तक वितरित की गई राशन सामग्री की मात्रा एवं उपभोक्ताओं की संख्या आदि की जानकारी ली।

कलेक्टर ने ग्राम मोड़ी में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के उर्वरक वितरण केन्द्र का निरीक्षण कर ई-टोकन के माध्यम से उर्वरक वितरण कार्य का अवलोकन भी किया। उन्होंने समिति प्रबंधक से उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति तथा अग्रिम उठाव के बारे में जानकारी ली।

कलेक्टर ने इस भ्रमण के दौरान शासकीय उमावि परिसर में स्थित सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 4 मोड़ी का निरीक्षण कर केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति, टीकाकरण, गरम पका भोजन वितरण, नाश्ता वितरण, बच्चों के वजन लेने एवं टीकाकरण पंजी का संधारण, शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों की जानकारी ली। कलेक्टर ने नियमित रूप से आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन की सराहना की। आंगनवाड़ी के बच्चों ने पुष्प गुच्छ भेंटकर कलेक्टर एवं एसपी का स्वागत् किया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राजीव गुप्ता, एसडीएम श्रीमती देवकुंवर सोलंकी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर द्वारा पशु आहार निर्माण यूनिट एवं गौ-पालन कैन्द्र का निरीक्षण- कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना एवं एसपी दिलीप सोनी ने ग्राम मोड़ी के समीप अनिल पाटीदार द्वारा स्थापित पशु आहार निर्माण यूनिट एवं गौ-पालन केन्द्र का निरीक्षण कर विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने पाटीदार द्वारा ग्रामीणों से ढ़ाई रूपए किलों के भाव से हरी मक्का के पौधें खरीदकर उन्हें अपनी यूनिट में लाकर पुश आहार साइनेज तैयार करने के कार्य की सराहना की। कलेक्टर ने इसके साथ ही पाटीदार द्वारा स्थापित गौ-पालन केन्द्र में गिर नस्ल की 58 गायों के पालन के कार्य का अवलोकन भी किया और गौपालन से हो रहे लाभ के बारे में चर्चा की। कलेक्टर ने ग्राम पायली में जुगलकिशोर पाटीदार द्वारा अपने खेत में साढ़े तीन हजार संतरे के पौधें लगाकर तैयार किये गए संतरा बागवान का निरीक्षण किया और संतरे के पौधें की खरीदी, लागत, बगीचा तैयार करने में आई लागत, फल बहार एवं विपणन की व्यवस्था आदि की जानकारी भी ली।

इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ बीएस सोलंकी, एसडीएम श्रीमती देवकुंवर सोलंकी, एसडीओपी देवनारायण यादव, उप संचालक कृषि गोपेश पाठक, उप संचालक उद्यानिकी अर्जुन राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जिले में फसल अवशेष एवं नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर डॉ. भरसट ने जारी किए आदेश

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग, भोपाल द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रदेश में फसल कटाई के पश्चात खेतों में बचने वाले ठूंठ एवं डंठल (पराली/नरवाई) को जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।

शासन के निर्देशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण एवं आगजनी की घटनाओं की रोकथाम, आमजन के स्वास्थ्य एवं जानमाल की सुरक्षा तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संपूर्ण झाबुआ जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में फसल अवशेष (पराली/नरवाई) जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किया है।

कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रॉ रीपर अनिवार्य- जारी आदेशानुसार जिले में फसलों की कटाई में उपयोग किए जाने वाले कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) अथवा स्ट्रॉ रीपर में से किसी एक मशीन का उपयोग अनिवार्य रहेगा। नरवाई से भूसा प्राप्त करने के इच्छुक कृषक स्ट्रॉ रीपर का उपयोग कर सकेंगे।

जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक कृषि अभियांत्रिकी, जिला झाबुआ को कंबाइन हार्वेस्टर के संचालन की निरंतर निगरानी करने तथा निर्धारित मशीनों के बिना संचालन पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

नरवाई जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति एवं पर्यावरण पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव- फसल अवशेष एवं नरवाई जलाने से मिट्टी में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीव एवं जैविक कार्बन नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। साथ ही वायु प्रदूषण एवं आगजनी की घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है।

कृषकों को सलाह दी गई है कि वे नरवाई जलाने के स्थान पर उसका उपयोग आच्छादन (मल्चिंग), स्ट्रॉ रीपर से भूसा तैयार कर पशु आहार के रूप में अथवा भूसे के विपणन से अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए करें।

कृषक खरीफ फसल की कटाई के पश्चात बिना जुताई किए खड़ी नरवाई में हैप्पी सीडर अथवा सुपर सीडर से सीधे बुवाई कर सकते हैं। इससे कृषि लागत में कमी आने के साथ मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त बेलर, रेकर एवं चॉपर मशीनों के माध्यम से नरवाई के बंडल तैयार कर उनका उपयोग औद्योगिक ईंधन, आच्छादन एवं भूसा निर्माण में किया जा सकता है।

नरवाई जलाने पर निर्धारित अर्थदण्ड- मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुरूप फसल अवशेष जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

- 02 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों पर प्रति घटना 2,500 रुपये अर्थदण्ड।
- 02 एकड़ से अधिक एवं 05 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों पर प्रति घटना 5,000 रुपये अर्थदण्ड।
- 05 एकड़ से अधिक भूमि वाले कृषकों पर प्रति घटना 15,000 रुपये अर्थदण्ड।

आदेश के पालन एवं निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त-आदेश में उल्लेखित शर्तों का जिले में पालन सुनिश्चित कराने के लिए उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जिला झाबुआ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कृषि विकास अधिकारी एवं क्षेत्रीय पटवारी द्वारा संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत किया जाएगा। तहसीलदार द्वारा संबंधित कृषक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए 07 दिवस के भीतर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

आदेश की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अन्य प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, समस्त तहसीलदार कार्यालयों, थाना कार्यालयों तथा ग्रामीण एवं नगरीय निकायों के सूचना पटल पर आदेश प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश 06 दिसंबर 2026 तक रहेगा प्रभावशील- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. भरसट द्वारा जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक विजय शर्मा द्वारा 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं भगवती ऑफसेट 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक - विजय शर्मा, मो.नं. 94250-22499, फोन 0734-2553435 प्रधान संपादक : शुभम ताम्रकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

चार मंजिला होटल नुमा भवन ढहाया- हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम की कार्रवाई

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह निगम की टीम ने जूना अखाड़े से जुड़े हरियाणा सेवा आश्रम में बने चार मंजिला होटलनुमा भवन को जमींदोज कर दिया। यह आश्रम महामंडलेश्वर ज्योतिगिरी जी महाराज का है। करीब 8 हजार वर्गफीट में बने इस भवन को हटाने के लिए निगम ने दो बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। चार पोकलेन मशीनों और एक जेसीबी की मदद से भवन को पूरी तरह ढहा दिया गया। इसका निर्माण करीब डेढ़ साल से चल रहा था।

सिंहस्थ के लिए आरक्षित जमीन पर बिना अनुमति किए गए निर्माणों को हटाने का अभियान अब तेज होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले माधवानंद आश्रम, शंकराचार्य मठ सहित कई स्थानों पर कार्रवाई हो चुकी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए शाही मस्जिद के हिस्से को भी हटाया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पैतृक मकान का एक हिस्सा भी सड़क चौड़ीकरण की जद में आने के कारण हटाया जा चुका है। नगर निगम की कार्रवाई से साफ है कि सिंहस्थ की तैयारियों के लिए चिह्नित जमीन और प्रस्तावित मार्गों पर बाधक निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई- नगर निगम के भवन अधिकारी राजकुमार राठौर के मुताबिक, सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माणों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम को अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। इसी के बाद निगम ने कार्रवाई शुरू की। हरियाणा सेवा आश्रम में बने नए भवन को तोड़ा गया, जबकि आश्रम के पुराने हिस्से को सुरक्षित रखा गया। भवन के दूसरी ओर लगा वॉटर सॉफ्टनर भी हटाया गया।

निगम के अनुसार, आश्रम में निर्माण हटाने के लिए पहले दो बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद शुक्रवार सुबह मशीनों के साथ निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। चार पोकलेन और एक जेसीबी की मदद से चार मंजिला भवन को पूरी तरह ढहा दिया गया।

2023 में लगी थी याचिका, शिप्रा प्रदूषण का मुद्दा भी उठा- सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माणों और शिप्रा नदी के प्रदूषण का मामला वर्ष 2023 में हाईकोर्ट पहुंचा था। उज्जैन निवासी सत्यनारायण सोमानी ने याचिका दायर कर बताया था कि शिप्रा नदी के दोनों किनारों पर 100 से 200 मीटर के दायरे में होटल, मठ, आश्रम, स्कूल और कॉलोनियों के निर्माण हो गए हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन निर्माणों से निकलने वाला सीवरेज सीधे शिप्रा नदी में मिल रहा है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। मामले की सुनवाई के बाद 5 मई को हाईकोर्ट ने नगर निगम को 15 जून तक अतिक्रमणों की सूची तैयार कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माणों को लेकर निगम की कार्रवाई तेज हुई है। इस मामले में नदी किनारे के निर्माणों के साथ ही सिंहस्थ के लिए आरक्षित भूमि पर किए गए निर्माण भी कार्रवाई के दायरे में आ रहे हैं। हालांकि, प्रत्येक निर्माण के मामले में अनुमति, भूमि की स्थिति और संबंधित आदेश के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

माधवानंद आश्रम की दो मंजिला इमारत भी ढहाई- हरियाणा सेवा आश्रम से पहले नगर निगम ने लाल पुल क्षेत्र में सिंहस्थ के लिए आरक्षित जमीन पर बन रहे माधवानंद आश्रम की दो मंजिला इमारत को भी ढहा दिया था। करीब 10 हजार वर्गफीट में बन रही इस इमारत को तोड़ने के लिए दो पोकलेन मशीनों और चार जेसीबी की मदद ली गई थी। करीब 25 दिन पहले हुई इस कार्रवाई में निर्माण को पूरी तरह हटाया गया था। इससे पहले 25 फरवरी 2026 को सिंहस्थ क्षेत्र में शंकराचार्य मठ और धर्मशालाओं सहित पांच संपत्तियों पर कार्रवाई की गई थी। लोहे के पुल के पास नरसिंह घाट जाने वाले रास्ते पर कर्कराज पार्किंग के नजदीक पुण्यानंद गिरि महाराज के आश्रम की तीन मंजिला इमारत भी कार्रवाई के दायरे में आई थी। करीब 15 हजार वर्गफीट में बनी इस इमारत में एसी और बिना एसी वाले कुल 54 कमरे थे। निगम की टीम ने एक दिन की कार्रवाई में भवन को करीब 70 प्रतिशत तक तोड़ दिया था। इन कार्रवाइयों के जरिए निगम सिंहस्थ के लिए आरक्षित भूमि पर बिना अनुमति किए गए निर्माणों को हटाने में जुटा है।

शाही मस्जिद पर कार्रवाई के दौरान हुआ था पथराव- सितंबर 2026 में सड़क चौड़ीकरण के लिए शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति बन गई थी। विरोध के बीच पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई थीं। बाद में मस्जिद प्रबंधन से जुड़े लोगों ने आगे आकर प्रभावित हिस्से को हटाने का काम किया। कार्रवाई के दौरान गुंबद और मीनार के कुछ हिस्से भी हटाए गए थे।

शाही मस्जिद का मामला सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले धार्मिक स्थलों के निर्माणों को लेकर चर्चा में रहा। इसके अलावा खड़े हनुमान मंदिर का बाहरी ढांचा भी हटाया गया था, जबकि प्रतिमा को सुरक्षित रखा गया। मदीना कॉलोनी और बेगम बाग क्षेत्र में भी मकान, गोदाम और अन्य निर्माणों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

सिंहस्थ से पहले जमीन खाली कराने की चुनौती- सिंहस्थ 2028 में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण, आवागमन और मेला क्षेत्र के विकास की योजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसे में सिंहस्थ के लिए आरक्षित जमीन पर हुए निर्माणों को हटाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अब तक आश्रमों, धार्मिक स्थलों और अन्य संपत्तियों पर हुई कार्रवाई से स्पष्ट है कि निगम ने अवैध निर्माणों को हटाने का अभियान जारी रखा है।

आज से घरों में शुरू होगा कुलदेवी पूजन

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शारदीय नवरात्रि में अब आज शनिवार से घरों में देवी पूजन और कन्या पूजन की शुरूआत हो जाएगी। सप्तमी तिथि दो दिन रहने से अष्टमी और नवमी की तारीख को लेकर श्रद्धालुओं में असमंजस है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, 18 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी और 19 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। वहीं, 20 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। ज्योतिष आचार्य पंडित विशाल शुक्ला ने बताया कि सप्तमी तिथि 17 अक्टूबर को सूर्योदय के साथ होने से इस दिन सप्तमी का व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा। सप्तमी तिथि 18 अक्टूबर को सुबह करीब 9 बजे तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को सुबह 8:27 बजे से शुरू होकर 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे तक रहेगी। ऐसे में अष्टमी का व्रत 18 अक्टूबर को रखना उत्तम माना गया है। नवमी तिथि 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे से शुरू होकर 20 अक्टूबर को दोपहर 12:50 बजे तक रहेगी। इस कारण नवमी का व्रत 19 अक्टूबर को किया जाएगा। हालांकि, पंचांगों में तिथियों की गणना के अंतर के कारण कुछ स्थानों पर अष्टमी और नवमी दोनों पर्व 19 अक्टूबर को भी मनाए जा सकते हैं। ज्योतिषी के अनुसार, नवरात्रि में अष्टमी युक्त नवमी व्रत की परंपरा है। ऐसे में अष्टमी और नवमी के व्रत एक ही दिन करने में कोई दोष नहीं है। दशमी तिथि 20 अक्टूबर को होने से इसी दिन दशहरा मनाया जाएगा। तिथियों को लेकर असमंजस के बीच श्रद्धालु अपने पंचांग और परंपरा के अनुसार पूजन-व्रत की तैयारियां कर रहे हैं।

सड़क निर्माण की स्थिति देखने पहुंचे अधिकारी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सिंहस्थ की तैयारियों के तहत शहर और आसपास चल रहे निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता का शुक्रवार को संभागायुक्त और कलेक्टर ने विभिन्न निर्माण स्थलों का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने शक्करवासा पंचक्रोशी मार्ग, पुलिया, त्रिवेणी स्थित नवग्रह शनि मंदिर के पीछे बन रहे ब्रिज और जीवनखेड़ी से शनि मंदिर को जोड़ने वाले एमआर-23 फोरलेन का निरीक्षण किया। संभागायुक्त आशीष सिंह ने शक्करवासा पंचक्रोशी मार्ग का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को सड़क का लेवल सही रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार हो, ताकि सड़क पर आवागमन के दौरान लोगों को परेशानी न हो। काम को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने नवग्रह शनि मंदिर के पीछे बन रहे नए ब्रिज का जायजा लिया। इंजीनियरों ने निर्माण की प्रगति और आगे होने वाले कामों की जानकारी दी। संभागायुक्त ने काम की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे और कार्य समय पर पूरे हो सकें। निरीक्षण के दौरान अपर मेला अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, इंजीनियर और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

रात की शयन आरती और सुबह की भस्म आरती में हुए शामिल अपर मुख्य सचिव

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने गुरुवार रात भगवान महाकालेश्वर की शयन आरती और शुक्रवार सुबह भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन किए। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रशासक प्रथम कौशिक ने उनका स्वागत किया।

भाई के आने पर हुई मृतक मजदूर की पहचान

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। कृषि उपज मंडी के पीछे धर्मशाला में मजदूरी के लिए आए युवक की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह भाई के आने पर उसकी पहचान की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मजदूर की मौत का खुलासा होगा।

चिमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि कृषि उपज मंडी गेट के पीछे धर्मशाला निर्माण के दौरान मजदूरी के लिए आए एक युवक की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक के संबंध में जानकारी जुटाना पर सामने आया कि उसे काम के लिए सराय से लाया गया था नाम पता मालूम नहीं है। पुलिस ने पहचान के प्रयास शुरू किया रात में पता चला कि मृतक पान बिहार चौकी क्षेत्र के ग्राम पद्मा खेड़ी का रहने वाला शंकर लाल पिता भवरलाल है। परिजनों से पुलिस द्वारा संपर्क किया गया आज सुबह भाई राजेश गुर्जर उज्जैन पहुंच और उसने शंकर की पहचान कर ली। भाई ने बताया कि शंकर दो बच्चों का पिता था और मजदूरी करता था वह गुरुवार सुबह मजदूरी के लिए उज्जैन आया था। पुलिस के अनुसार उसके साथ काम कर रहे मजदूरों का कहना था कि अचानक चक्कर आने के बाद गिरा था। पुलिस को आशंका है कि मजदूर शंकर को हार्ट अटैक हुआ है जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर होगा फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है।

दिग्विजय सिंह निकालेंगे उज्जैन से अयोध्या तक सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा

20 अक्टूबर से होगी शुरुआत, वोट चोरी और राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे उठाएगी कांग्रेस

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा 20 अक्टूबर को उज्जैन से अयोध्या तक सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी। करीब 930 किलोमीटर की इस यात्रा में वोट चोरी और चंदा चोरी के मुद्दे उठाए जाएंगे। यात्रा से पहले शुक्रवार को बालाजी गार्डन में पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया।

यात्रा से जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर, पैम्फलेट और थीम सॉन्ग भी जारी किए गए हैं।भूमिपूजन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक महेश परमार, नेता प्रतिपक्ष रविराय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। विश्व कल्याण की कामना से असंख्य पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण 20 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से होगा। इसकी जिम्मेदारी गृहस्थ संत ब्रह्मलीन दद्दा के शिष्य मंडल के शिष्य सुरेंद्र सुहाने को सौंपी गई है।

वोट और चंदा चोरी पर सरकार को घेरेंगे- पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह वोट चोरी और चंदा चोरी के मुद्दों को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी से लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, जबकि चंदा चोरी से लोगों की धार्मिक आस्था प्रभावित होती है। शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और जवाबदेही जरूरी है।

महाकाल दर्शन के बाद शुरू होगा सफर- विधायक महेश परमार के अनुसार, दिग्विजय सिंह 18 अक्टूबर की रात उज्जैन पहुंचेंगे। 20 अक्टूबर को चिंतामन गणेश मंदिर में दर्शन के बाद बालाजी गार्डन में पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद यात्रा शुरू होगी और भगवान महाकाल के दर्शन किए जाएंगे। यात्रा के दौरान दशहरे पर कम्प्यूटर बाबा हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी करेंगे।

महाकाल मंदिर से यात्रा पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, कमरी मार्ग चौराहा, टंकी चौराहा, मिर्जा नईम बेग मार्ग, तेलीवाड़ा, कंठाल, निजातपुरा, कोयला फाटक, नगर निगम, गाड़ी अड्डा, दरगाह मंडी और कानीपुरा रोड होते हुए तराना रोड स्थित श्री साई कुंज कॉलोनी पहुंचेगी। यहां रात्रि भोजन और विश्राम होगा।

एमपी से यूपी पहुंचेगी यात्रा- यात्रा उज्जैन से शुरू होकर तराना, शाजापुर, सारंगपुर, खुजनेर, राजगढ़, चाचौड़ा, आरोन, अशोकनगर और चंदेरी से गुजरेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में तालबेहट, जेरोन और ओरछा होते हुए चिरगांव, उरई, कालपी, कानपुर देहात, लखनऊ देहात और बाराबंकी से अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा में ओरछा स्थित रामराजा सरकार मंदिर के दर्शन करते हुए अयोध्या के श्रीराम मंदिर तक पहुंचने का कार्यक्रम है।

महिला बाल विकास द्वारा सड़क पर रहने वाले गरीब बच्चों का किया सर्वे

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। महिला बाल विकास ने जोखिम ग्रस्त बालको के सर्वे कराकर सड़क पर रहने वाले बच्चे ओर सड़क पर रहने वाले परिवारो के बच्चों को जिला बाल संरक्षण अधिकारी बृजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया।

जिसमें शहरी परियोजना क्रमांक 1 परियोजना अधिकारी प्रियका जायसवाल के द्वारा पर्यवेक्षक व आंगनवाडी कार्यकर्ताओ के साथ कोस्मोस मॉल के सामने, काला पत्थर, नानाखेडा बस्ती में सड़क पर निवासी अस्थाई बस्तियो में लगभग 40 बच्चे चिंन्हाकित किये गये। व शहरी परियोजना क्रमांक 4 परियोजना अधिकारी अर्चना दलाल के मार्गदर्शन में पर्यवेक्षक वंदना गुप्ता व आंगनवाडी अमले द्वारा कार्तिक मेला ग्राउंड, ईमली चौक में सड़क पर निवासी अस्थाई बस्तियो में लगभग 60 बच्चे चिंन्हाकित किये गये।

जिनकी सर्वे जानकारी प्रारूप 2 में भरकर आगामी कार्यवाही हेतु तैयार की जावेगी।

विशेष अभियान अंतर्गत एक दिवस में 100 से अधिक बच्चो को चिन्हाकित किया गया। परियोजना खाचरौद 2 परियोजना अधिकारी मुकेश वर्मा के मार्गदर्शन में पर्यवेक्षक मीनु गुप्ता व आंगनवाडी अमले द्वारा 17 ऐसे बालको को चिन्हित किया गया। संपूर्ण अभियान में आईसीपीएस के संरक्षण अधिकारी सुरेन्द्र कुमार शर्मा व सामाजिक कार्यकर्ता गौरव मित्तल द्वारा प्रभावी सहयोग व ईनीशीएटीव लेते हुए बस्तियो में प्रभावी संवाद भी किया गया। अभियान में परियोजना उज्जैन शहर क 1 पर्यवेक्षक सरिता व आंगनवाडी कार्यकर्ता शहर 4 सरला जोशी द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया।

प्रदूषण से बीमार होने वालों की अब चरक भवन में होगी जांच

जिला अस्पताल में शुरू हुआ चेस्ट क्लिनिक-अगले वर्ष फरवरी तक मिलेगी जांच

उज्जैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। वायु प्रदूषण से सांस संबंधी परेशानी और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए जिला चिकित्सालय के चरक भवन में चेस्ट क्लिनिक शुरू किया गया है। यहां आज शुक्रवार से आगामी 28 फरवरी तक मरीजों की जांच, उपचार और परामर्श किया जाएगा। चरक अस्पताल भवन में शुरू हुई क्लीनिक में सभी आयु वर्ग के लोग इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे और यहां,धूम्रपान, घरेलू ईंधन के धुएं, धूल और औद्योगिक प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले लोगों की विशेष रूप से जांच की जाएगी। मरीजों में बीमारी के लक्षणों की पहचान कर जोखिम का आकलन किया जाएगा। जरूरत के अनुसार इलाज के साथ आगे की जांच और फॉलोअप भी किया जाएगा।

बीमारियों से बचाव की भी मिलेगी सलाह- सिविल सर्जन डॉ. संगीता पलसानिया ने बताया कि क्लिनिक में मरीजों को वायु प्रदूषण से बचाव के तरीके भी बताए जाएंगे। इसमें धूम्रपान छोड़ने, स्वच्छ ईंधन अपनाने, घरों में हवा की उचित आवाजाही रखने और अधिक प्रदूषण वाले दिनों में सावधानी बरतने की सलाह शामिल है। गंभीर या विशेष उपचार की जरूरत वाले मरीजों को संबंधित विशेषज्ञों के पास भेजा जाएगा। क्लिनिक शुरू करने का उद्देश्य प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की समय पर पहचान कर मरीजों को उपचार उपलब्ध कराना और लोगों को इनके प्रति जागरूक करना है।

उज्जैन-आगर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा

उज्जैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के घोंसला के समीप तराना फंटे पर और शाम को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार को बचाने में बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और कुछ यात्री घायल हुआ है। राघवी थाना पुलिस ने बताया कि आगर से उज्जैन की ओर आ रही एक निजी बस (शर्मा ट्रेवल्स, बस क्रमांक स्क्क 70 क्क0 161) के चालक में बाइक सवार को बचाने का प्रयास किया जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर खाई में उतर गई। सड़क किनारे दो युवक खड़े थे जो हादसे का शिकार होगा दोनों की मौके पर मौत हो गई जिनकी पहचान महेश पिता बापूजी और मोहन पिता मांगीलाल के रूप में हुई है दोनों ग्राम ब्राह्मण बड़ोदिया के रहने वाले थे और ग्राम ठुकराल जा रहे थे। बस में सवाल कुछ यात्री भी घायल हुए हैं जिन्हें मामूली चोट लगा बताया जा रहा है। घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रशासन द्वारा घायलों के समुचित उपचार और मृतकों के परिजनों को सहायता पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

माकड़ोन अनाज मंडी में लोकायुक्त का छापा

उप निरीक्षक और आउटसोर्स कर्मचारी की रिश्वत लेते पकड़ाए

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार सुबह माकड़ोन अनाज मंडी में कार्रवाई करते हुए मंडी उप निरीक्षक रोशन आर्य और उसके साथी आउटसोर्स कर्मचारी संतोष भाटी को 4 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोप है कि मंडी उप निरीक्षक सोयाबीन खरीदने वाले व्यापारी से प्रत्येक बोरी के हिसाब से 10 रुपये की मांग कर रहा था। रिश्वत नहीं देने पर सोयाबीन से भरी गाड़ी नहीं जाने देने की बात कही जा रही थी।

लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, ग्राम रूपाखेड़ी निवासी व्यापारी योगेश राठौर ने 14 अक्टूबर को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार दीक्षित से शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह माकड़ोन मंडी से सोयाबीन खरीदता है और मंडी उप निरीक्षक रोशन आर्य उससे प्रत्येक बोरी के हिसाब से 10 रुपए मांगता है। व्यापारी का कहना था कि मंडी टैक्स देने के बावजूद उससे अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही है।

सत्यापन के बाद बिछाया जाल- शिकायत मिलने के बाद उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक ने उसका सत्यापन किया। शिकायत सही पाए जाने पर लोकायुक्त की 10 सदस्यीय टीम ने आज सुबह ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। टीम मंडी परिसर पहुंची और जैसे ही व्यापारी ने 4,000 की रिश्वत रोशन आर्य को दी, उसने रकम अपने साथी आउटसोर्स कर्मचारी संतोष भाटी को थमा दी। इसी दौरान लोकायुक्त टीम ने दोनों को पकड़ लिया और रिश्वत की राशि बरामद कर ली।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण- कार्रवाई में रोशन आर्य, पिता पूनमचंद आर्य, निवासी ग्वालियर तथा संतोष भाटी, पिता प्रहलाद भाटी, निवासी माकड़ोन को पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

10 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई- लोकायुक्त की ट्रैप टीम में डीएसपी राजेश पाठक, डीएसपी दीपक सेजवार, प्रधान आरक्षक हितेश ललावत, आरक्षक शिवकुमार शर्मा, श्याम शर्मा, इसरार खान, उमेश जाटव सहित अन्य सदस्य और साक्षीगण शामिल रहे।

मुख्यमंत्री के गजनी खेड़ी में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का विधायक श्री पडया, कलेक्टर, एसपी ने निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए

उज्जैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गजनी खेड़ी में प्रस्तावित आगमन को लेकर तैयारी शुरू हो गई। शुक्रवार को गजनी खेड़ी माता मंदिर परिसर में कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड स्थल का विधायक श्री जितेंद्र पड्या, कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह, एसपी श्री प्रदीप शर्मा ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम स्थल पर सुगम आवागमन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, आवश्यक बेरीकेर्डिग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिएं। पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा ने सुरक्षा दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त संख्या में बैरिकेडिंग करने और पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती करने के निर्देश दिएं। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री श्रेयांश कूमट, एएसपी कारणदीप सिंह, बड़नगर एसडीएम श्री धीरेंद्र पाराशर, नागदा एसडीएम श्रीमती रंजना पाटीदार एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

महाकाल की राजसी सवारी का आकाशवाणी उज्जैन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। विगत 07 सितम्बर को महाकाल की राजसी सवारी का अनवरत 8 घंटे आकाशवाणी उज्जैन ने आँखों देखा हाल प्रसारित कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस सजीव प्रसारण में मध्य प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी 19 केन्द्रों (विविध भारती सहित) की सहभागिता रही, जिसे हर अंचल के श्रोताओं ने रेडियो के साथ %न्यूज़ ऑन एआईआर% एप्लिकेशन के माध्यम से सुना गया। इसके पूर्ववर्ती वर्ष में आकाशवाणी इन्दौर ने वर्ल्ड रिकार्ड हासिल किया था, जिसे इस वर्ष आकाशवाणी उज्जैन ने पिछले रिकार्ड को तोड़ दिया। इसमें कार्यक्रम अधिकारी श्री ब्रह्मप्रकाश चतुर्वेदी ने कमान संभाली थी, आकाशवाणी इन्दौर में और अब वर्तमान में आकाशवाणी उज्जैन में पदस्थ होकर इस ऐतिहासिक खेलों से इतर आँखों देखा हाल प्रसारित करने में दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए धार्मिक आयोजन में महती भूमिका निभाई। जिसकी परिणति है कि आकाशवाणी उज्जैन परिसर में गरिमामय समारोह का आयोजना किया गया जिसके मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक श्री राकेश गुप्ता एवं पुलिस अधिक्षक श्री प्रदीप शर्मा ने की ।

मायके में रहने वाली महिला की कुएं से मिली लाश

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मायके में रहने वाली महिला शाम को अचानक लापता हो गई थी परिजनों ने तलाश शुरू की तो घर से कुछ दूरी पर मंदिर के पास कुएं से उसकी लाश बरामद हो गई। महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था ससुराल वालों ने आरोपी से समझौता कर महिला को घर से निकाल दिया था। महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ भरण पोषण का केस भी लगा दिया था।

मक्सी रोड स्थित पंचकुआं शंकरपुर में रहने वाली रानी पति विनोद मोरी 27 साल 1 साल से अपने माता-पिता और भाई के साथ रह रही थी। गुरुवार शाम को वह अचानक लापता हो गई। परिवार ने तलाश शुरू की। शाम के समय रानी घर से कुछ दूरी पर बने मंदिर पर दर्शन करने जाती थी। भाई दिलीप और आकाश उसकी तलाश में मंदिर के पास पहुंचे लेकिन रानी दिखाई नहीं दी वापस लौटते समय मंदिर के पास बने हुए के बाहर रानी की चप्पल पड़ी थी। शंका होने पर भाई विनोद ने कुएं में झांका तो उसने रानी को डूबा हुआ देखा। मामले की सूचना पुलिस को दी गई क्षेत्र के लोग भी एकत्रित हो गए। रात में रानी का शव बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। पंवासा पुलिस ने शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू की।

भरण पोषण का लगाया था केस

ससुराल वालों ने घर से निकाला तो रानी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ न्यायालय में केस लगा दिया था। भरण पोषण की मांग की गई थी। 2 दिन पहले तारीख पेशी होने पर न्यायालय गई थी, जहां सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई थी। लेकिन रानी परेशान दिखाई दे रही थी। पंवासा थाना प्रभारी गेमर मंडलोई द्वारा परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच का शुरू करने की बात कही है।

होटल में शारिरीक शोषण कर ठगे 14 लाख

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। फेसबुक पर खुद को आर्मी मेन बताकर महिला केयर टेकर से दोस्ती कर शादी का झांसा दिया और उज्जैन की होटल में लेकर आया, जहां शारिरीक शोषण करने के साथ 14 लाख रूपये भी ठग लिये। 4 साल पहले हुये शोषण की शिकायत महिला ने देवासगेट थाने आकर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि इंदौर के सूरज नगर में रहने वाली 38 वर्षीय महिला केयर टेकर है। वर्ष 2022 में उसकी दोस्त फेसबुक के माध्यम से उत्तरप्रदेश के चंदौली में रहने वाले अजय ओझा से हुई थी। उसने खुद को आर्मी मेन बताया था और अविवाहित होने के साथ फेसबुक पर फोटो भी लगा रखा था। दोनों की बातचीत शुरू हुई। मामला शादी तक पहुंच गया। अजय उसे 25 सितंबर 2022 को उज्जैन लेकर आया। देवासगेट स्थित होटल भारती में रूम लिया और महिला का शारीरिक शोषण किया। चार सालों तक शादी का झांसा देता रहा, उसने महिला से सोने की चेन खरीदने, शोक पूरे करने और अन्य खरीददारी के नाम पर 14 लाख ले लिये। कुछ दिनो पहले महिला का पता चला कि अजय की पहली पत्नी का निधन हो चुका है, वह दूसरी शादी कर चुका है। केयर टेकर ने शादी की बात कहीं तो अजय ने इंकार कर दिया। अपने साथ हुये शारिरीक शोषण और 14 लाख की ठगी होने पर केयर टेकर महिला अभिभाषक के साथ उज्जैन पहुंची और देवासगेट थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी नरेन्द्रसिंह परिहार ने बताया कि मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश में एक टीम उत्तरप्रदेश भेजी जायेगी।